प्रेरणा

RNI No. UPHIN/2000/3766 • ISSN No. 2581-3528 ₹:20

केशव संवाद

(दिसम्बर–2022 / जनवरी–2023, संयुक्तांक)

भारत करेगा G20 की अध्यक्षता

जनवरी 2023, पौष–माघ विक्रम सम्वत् 2079

हिन्दी पंचांग

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
शु 25 / दशमी 10 1 ○ मेष ☆ अश्विनी मु 8	शु 26 / एकादशी 11 2 ○ मेष 20:52 ☆ भरणी मु 9	शु 27 / द्वादशी 12 3 ○ वृषभ ☆ कृत्तिका मु 10	शु 28 / त्रयोदशी 13 4 ○ वृषभ ☆ रोहिणी मु 11	शु 29 / चतुर्दशी 14 5 ○ वृषभ 08:06 ☆ मृगशीर्षा मु 12	30 / पूर्णिमा 15 6 ○ मिथुन ☆ आर्द्रा मु 13	कृ 32 / प्रतिपदा 1 माघ 7 ○ मिथुन 20:24 ☆ पुनर्वसु मु 14
कृ 33 / द्वितीया 2 8 ○ कर्क ☆ पुष्य मु 15	कृ 33 / द्वितीया 2 9 ○ कर्क ☆ आश्लेषा मु 16	कृ 34 / तृतीया 3 10 ○ कर्क 09:01 ☆ आश्लेषा मु 17	कृ 35 / चतुर्थी 4 11 ○ सिंह ☆ मघा मु 18	कृ 36 / पंचमी 5 12 ○ सिंह 21:00 ☆ पूर्व फाल्गुनी मु 19	कृ 37 / षष्ठी 6 13 ○ कन्या ☆ उत्तर फाल्गुनी मु 20	कृ 38 / सप्तमी 7 BH 14 पोंगल ○ कन्या ☆ हस्त मु 21
कृ 39 / अष्टमी 8 15 मकर संक्रांति ○ तुला ☆ चित्रा मु 22	कृ 40 / नवमी 9 16 ○ तुला ☆ स्वाति मु 23	कृ 41 / दशमी 10 17 ○ तुला 13:00 ☆ विशाखा मु 24	कृ 42 / एकादशी 11 18 ○ वृश्चिक ☆ अनुराधा मु 25	कृ 43 / द्वादशी 12 19 ○ वृश्चिक 15:18 ☆ ज्येष्ठा मु 26	कृ 44 / त्रयोदशी 13 20 गुरु गोबिंदसिंह जयंती ○ धनु ☆ मूल मु 27	46 / अमावस्या 30 21 ○ धनु 14:53 ☆ पूर्वाषाढ़ा मु 28
शु 16 / प्रतिपदा 1 22 ○ मकर ☆ श्रवण मु 29	शु 17 / द्वितीया 2 23 ○ मकर 13:51 ☆ धनिष्ठा रज्जब मु 1	शु 18 / तृतीया 3 24 ○ कुंभ ☆ शतभिषा मु 2	शु 19 / चतुर्थी 4 25 ○ कुंभ 14:29 ☆ पूर्वभाद्रपदा मु 3	शु 20 / पंचमी 5 BH 26 गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी ○ मीन ☆ उत्तरभाद्रपदा मु 4	शु 21 / षष्ठी 6 27 ○ मीन 18:36 ☆ रेवती मु 5	शु 22 / सप्तमी 7 BH 28 ○ मेष ☆ अश्विनी मु 6
शु 23 / अष्टमी 8 29 ○ मेष ☆ भरणी मु 7	शु 24 / नवमी 9 30 ○ वृषभ ☆ कृत्तिका मु 8	शु 25 / दशमी 10 31 ○ वृषभ ☆ रोहिणी मु 9				

○ : चंद्र राशि, ☆ : नक्षत्र, मु : हिज्रा कैलेंडर, + : आधी रात्रि के बाद

जनवरी 2023 त्यौहार

02	सोमवार	पौष पुत्रदा एकादशी
04	बुधवार	प्रदोष व्रत
06	शुक्रवार	शाकम्भरी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, अन्वाधान
07	शनिवार	इष्टि
10	मंगलवार	सकट चौथ, लम्बोदर संकष्टी चतुर्थी
15	रविवार	मकर संक्रान्ति, पोंगल
18	बुधवार	षटतिला एकादशी
19	बृहस्पतिवार	प्रदोष व्रत
21	शनिवार	मौनी अमावस, दर्श अमावस्या, अन्वाधान, माघ अमावस्या
22	रविवार	माघ नवरात्रि, इष्टि
23	सोमवार	चन्द्र दर्शन
26	बृहस्पतिवार	वसन्त पञ्चमी
28	शनिवार	रथ सप्तमी, भीष्म अष्टमी

केशव संवाद

RNI No. UPHIN/2000/3766

ISSN No. 2581-3528

दिसम्बर 2022/जनवरी 2023

वर्ष : 22 अंक : 12

अणंज कुमार त्यागी
अध्यक्ष
प्रे. शो. सं. न्यास

संपादक
कृपाशंकर

कार्यकारी संपादक
डॉ. प्रियंका सिंह

संपादक मंडल
डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. अखिलेश मिश्र, डॉ. नीलम कुमारी, प्रो. अनिल निगम, डॉ. मनमोहन सिंह, अनीता चौधरी, अनुपमा अग्रवाल, अमित शर्मा

पृष्ठ संयोजन
वीरेंद्र पोखरियाल

संपादकीय कार्यालय
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास
सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा -201301
फोन न. 0120 4565851, 2400335
ईमेल : keshavsamvad@gmail.com
वेबसाइट : www.prernasamvad.in

स्वामी पंकज कुमार की ओर से मुद्रक/प्रकाशक सुखवीर प्रकाश द्वारा चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा से मुद्रित तथा केशव भवन 105, आर्यनगर सूरजकुंड रोड मेरठ से प्रकाशित

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा मेरठ की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा। संपादक

विषय सूची

भूकंप का विज्ञान : कहां, क्यों और कैसे	- पूनम कुमरिया	05
विश्व का नेतृत्व करने का स्वर्णिम अवसर	-डॉ. अनिल निगम	06
भारत के महत्व को रेखांकित करता जी-20 सम्मेलन	- आशीष कुमार	08
मीठी यादों में बसा एक लाल	-नरेन्द्र भदौरिया	10
वर्ष 2023 आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए एक...	- प्रहलाद सबनानी	12
हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उपासक - मालवीय जी	- मृत्युंजय दीक्षित	14
प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय सोच से ही भारत आत्मनिर्भर	- अदिति अग्रवाल	17
समान नागरिक संहिता पर संसद के गरमाने का औचित्य	- प्रमोद भार्गव	18
धार्मिक तीर्थ स्थानों के कायाकल्प से मजबूत हो रहा ...	- बिभाकर झा	20
भविष्य के भारत में शिक्षक की भूमिका	- डॉ. उर्विजा शर्मा	21
कौन वास्तव में हमारे देश के संविधान की आत्मा...	- पंकज जयस्वाल	22
इमामों को वेतन तो मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं ?	- डॉ. प्रीता पंवार	24
रोड शो से सँवरता उत्तर प्रदेश का निवेश परिवेश	- डॉ. मनमोहन सिंह	26
जब भी इसे पढ़ती हूँ, कुछ नया पाती हूँ!!	- नीलम भागी	28
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : भविष्य का भारत	- मोहित कुमार	30
आदर्श हिन्दू परिवार	- सतीश शर्मा	32
सोशल मीडिया की शक्ति	- शिल्पी जिंदल	34
पत्रिका के नवम्बर अंक की समीक्षा	- सतीश शर्मा	35

पाठकगण पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया, 'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से ई-मेल (keshavsamvad@gmail.com) के माध्यम से भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।

ISSN No. 2581-3528

संपादकीय...

भारत ने बीते कुछ वर्षों से एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की है जिसकी सकारात्मकता फलीभूत होती दिखाई पड़ रही है। सदियों से विश्व को ज्ञान योग आयुर्वेद जैसी अनेक विधाओं को देने वाला भारत आज एकाग्रता से बौद्धिक संपदा का अधिक दक्षता से उपयोग कर रहा है। जहां एक तरफ भारत को जी-20 की अध्यक्षता का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ वहीं विश्व में घटित होने वाली अनेकों समस्याओं पर भारत की राय अहम होती है। भारत की समृद्धि ज्ञान परंपरा व संस्कृत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा तभी विदेशों में बसने वाले भारतीय भी अपनी सांस्कृतिक समृद्धता के साथ जहां भी गए वहां अपने आदर्शों को स्थापित किया। उनके संस्कारों में शिक्षा व आचरण की सदगति बसती है तभी तो सुंदर पिचाई, राजा कृष्णमूर्ति जैसे अनेकों नाम ने विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाई है। जिस देश ने हम पर लगभग सैकड़ों वर्ष तक राज किया उसी देश का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति है।

आज भारत विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन कर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र व राज्य कृत संकल्पित है। इसमें सबसे तेजी से कार्यशील उत्तर प्रदेश राज्य पर्याप्त सदाशयता और परहित भाव के दृष्टिगत उचित दिशा में अग्रसर हैं। नीति और नियत की पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निवेशकों के लिए स्वर्णिम द्वार खोल दिए हैं। संकल्प की शक्ति से नकारात्मकता के भाव को समाप्त करते हुए उचित अवसर एवं संभावनाओं के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सभी राज्यों के लिए एक रोल मॉडल की भूमिका में नजर आ रहा है। वर्तमान में जहां एक और आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र के साथ विकास की गति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है वहीं सुरक्षा व सुशासन होने से बड़ी संख्या में निवेशक आकर्षित हो रहे। यही नहीं अन्य निवेशक भी अपने अनुभव के साथ दूसरे निवेशकों को प्रोत्साहित भी कर रहे। उत्तर प्रदेश की टीम ने 16 देशों के 21 शहरों में जाकर वहां से सात लाख करोड़ के निवेश भी लेकर आई है। वही दूसरी तरफ योगी जी ने मुंबई जाकर घरेलू निवेशकों को आमंत्रित किया और इसी कुशल नेतृत्व का परिणाम यह रहा कि ट्विटर पर हैश टैग योगीनॉमिक्स टॉप ट्रेंड पर रहा। जिसे अनेकों यूजर्स ने लाइक और रिट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक नीतियों को सराहा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश राज्य की यह भूमिका भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती लाएगी क्योंकि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र में ही समग्र विकास की अवधारणा निहित है। भारत की विविधता में एकता उसके जीवन मूल्यों में परिलक्षित होती है जिसके कारण ही वह आज मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आ रहा है। केशव संवाद का यह संयुक्ताक उन सभी महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है जिसमें भारत की नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।

संपादक

ISSN No. 2581-3528

भूकंप का विज्ञान : कहां, क्यों और कैसे

पूनम कुमरिया

भूकंप : एक परिचय – भूकंप तब होता है जब दो पृथ्वी के ब्लॉक अचानक एक दूसरे के पीछे खिसक जाती है। भूकंप प्रदर्शित करते हैं कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह बनी हुई है, आंतरिक शक्तियों द्वारा प्रत्येक दिन बदलती रहती है।

भूकंपीय स्टेशनों के विश्वव्यापी नेटवर्क द्वारा हर साल दस लाख से अधिक भूकंप दर्ज किए जाते हैं। इस नेटवर्क के साथ, सभी भूकंपों की सटीक स्थिति, गहराई और परिमाण को मानचित्रों पर अंकित किया जाता है।

जब भूकंप आता है तो पृथ्वी क्यों हिलती है? : पृथ्वी की चार प्रमुख परतें हैंरू आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और मेंटल का शीर्ष हमारी ग्रह की सतह पर एक पतली त्वचा का बना हुआ है। लेकिन यह त्वचा एक ही टुकड़े में नहीं है– यह एक पहेली की तरह कई टुकड़ों से बना है पृथ्वी की सतह को ढकने के लिए। हम इन पहेली टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और प्लेटों के किनारों को प्लेट कहते हैं सीमाएँ। प्लेट की सीमाएं कई भ्रंश से बनी हैं, और दुनिया भर में अधिकांश भूकंप यही पर आते हैं। चूँकि प्लेटों के किनारे खुरदरे होते हैं, वे अटक जाते हैं जबकि बाकी की प्लेट चलती रहती हैं। अंत में, जब प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तब प्लेट के किनारो भ्रंश से अलग होने लगते हैं और भूकंप आता है।

जबकि भ्रंश के किनारे आपस में चिपके हुए हैं, और शेष ब्लॉक गतिमान है, यह ऊर्जा ब्लॉक को स्लाइड करने का कारण बनती है। गतिमान ब्लॉक अंत में घर्षण को खत्म कर देता है और संचित ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा सभी दिशाओं में भ्रंश से बाहर की ओर विकीर्ण होती है। उदाहरण के लिए जैसा एक तालाब पर लहरों की तरह तरंगों का रूप प्रतिबिंबित होता है। भूकंपीय तरंगें चलती हैं तो पृथ्वी को हिलाती हैं और जब लहरें पृथ्वी की सतह पर पहुँचती हैं, तो वे जमीन और उस पर किसी भी चीज़ को हिला देती हैं जैसे हमारे घर और हम! जब जब पृथ्वी में टेकटोनिक प्लेट्स हिलती हैं भूकंप के झटके महसूस किये जाते हैं।

भूकंप की तीव्रता मानव जीवन पर भूकंप के प्रभावों के संबंध में मापी जाती है। आमतौर पर विनाश का वर्णन इमारतों, बांधों, सड़कों आदि को हुए नुकसान के रूप में किया जाता है। भूकंपों को यंत्रों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें सीस्मोग्राफ कहा जाता है। उनके द्वारा की जाने वाली रिकॉर्डिंग सीस्मोग्राम कहलाती है।

भूकंप से सुरक्षा : भूकंप वैश्विक आबादी के बड़े हिस्से के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। हर साल बड़े भूकंपों के कारण हजारों लोगों की मौत हो जाती है। भारत में अबतक सबसे ज्यादा भूकंप आने की घटनाएं हिमालय पर्वत और इसके आसपास के इलाकों में होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग चार करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियाई प्लेट इसी स्थान पर एक दूसरे से टकराए थे, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। यह हर साल लगभग ऊपर उठती है। इसी हलचल की वजह से इस इलाके में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। हिमालय और इसके आसपास के भारत में आने वाले हिस्से में हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और कई उत्तर–पश्चिमी राज्य आते हैं।

भूकंप हमेशा से आते रहे हैं। हमें यह सीखना है, भूकंप में अपने को बचाना। आपदा प्रबंधन के नियमों का पालन बहुत जरूरी है। स्कूल और कॉलेज में इसके बारे में सीखना भी आवश्यक हैं। तभी हम समाज को इसके विनाश से बचा सकते हैं।

(लेखिका मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

ISSN No. 2581-3528

विश्व का नेतृत्व करने का स्वर्णिम अवसर

प्रो. (डॉ.) अनिल कुमार निगम

जी–20 का नेतृत्व मिलने के साथ ही भारत के पास विश्व को नेतृत्व प्रदान करने का स्वर्णिम अवसर आ गया है। रूस के राष्ट्रपति ब्लादमिर पुतिन ने भी भारत को पत्र लिखकर उम्मीद जताई है कि वह विश्व की अनेक समस्याओं का हल निकालने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत को जी 20 की अध्यक्षता ऐसे समय में मिली है, जब विश्व की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है। समृद्ध ज्ञान परंपरा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के पास विश्व गुरू के रूप में खुद को साबित और स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से घोषणा की है कि 50 से अधिक शहरों में 200 से ज्यादा आयोजन किए जाएंगे, उससे यह आभास हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी–20 में भारत की भूमिका को लेकर बेहद सजग और सतर्क हैं।

भारत में अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को जी–20 सम्मेलन आयोजित होगा। पहली दिसंबर से इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी भारत को मिल चुकी है। ध्यातत्व है कि विश्व की आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है और यहां भाषाओं, धर्मों,रीति–रिवाज और विश्वास की विशाल विविधता है। जी–20 एक वैश्विक आर्थिक सहयोग का बड़ा एवं प्रभावशाली संगठन है। यह विश्व की जीडीपी का लगभग 85 प्रतिशत, व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो–तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका नाममात्र की रह गई है, उसे देखते हुए आगामी समय में जी–20 की भूमिका अधिक सशक्त होने की संभावना बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों ने न केवल भारत का लोहा स्वीकार किया है बल्कि उनको भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं।

जी–20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत को विश्व में अपनी छवि मजबूत बनाने का सुअवसर मिला है। हालांकि इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडोनशिया में आयोजित जी–20 शिखर सम्मेलन से कर दी है। उन्होंने इस दौरान देश के अलग–अलग हिस्सों में बने स्वदेशी उत्पाद के तोहफे न केवल दिग्गज नेताओं को भेंट किए बल्कि जी–20 का 2023 का लोगो जारी किया, जिसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को शामिल कर विश्व को संदेश भी दे दिया कि जी–20 पर भारत की गहरी छाप पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने कमल के फूल को निरंतर प्रगति का प्रतीक बताया है।

रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ एक बार फिर 'नख दंत' विहीन संस्था साबित हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन विश्व में शांति बनाए रखने के लिए

ISSN No. 2581-3528

किया गया था। लेकिन 1945 के बाद खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान पर आक्रमण, तिब्बत पर चीन का अतिक्रमण, भारत–चीन, भारत–पाकिस्तान, करगिल युद्ध जैसे अनेक युद्ध हो चुके हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र इन युद्धों को रोकने में पूरी तरह से नाकारा साबित हुआ है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता पर बार–बार सवाल उठता रहा है।

आज भारत विश्व की तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। वर्ष 2020 में कोविड महामारी का प्रकोप जिस तरीके से भारत में आया था, उससे ऐसा आभास हो रहा था कि 133 करोड़ की आबादी में बहुत ज्यादा लोग काल कवलित होंगे, लेकिन भारत ने जिस तरीके से खुद को संभाला, उसे संपूर्ण विश्व समुदाय ने देखा। उसके पश्चात भारत ने कोविड महामारी से निपटने के लिए कोविड वैक्सीन को न केवल अपने नागरिकों को बचाने के लिए विकसित की बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों सहित विश्व के अनेक देशों को खेपें भेजकर वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश भी दिया।

यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर विश्व समुदाय को भारत से बहुत अपेक्षाएं रही हैं। रूस भारत का पारंपरिक मित्र रहा है। भारत और रूस के बीच में रक्षा और व्यापार संबंधी अत्यंत सशक्त संबंध रहे हैं। अमेरिका और नाटो देशों ने रूस पर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। बाजवूद इसके भारत ने रूस से क्रूड आयल खरीदा। यही नहीं, इंडानेशिया में जी–20 की समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कह दिया कि यह समय युद्ध का नहीं है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, समस्याओं का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए।

वास्तविकता तो यह है कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित जी–20 देशों की शिखर बैठक में दुनिया को महाशक्ति बनने की ओर बढ़ते भारत की एक शानदार झलक देखने को मिली। जी–20 की अध्यक्षता मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर जी–20 को विश्व कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। निःसंदेह, जी–20 की अध्यक्षता मिलना वैश्विक फलक पर जहां भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, वहीं अगला एक वर्ष नई दिल्ली के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण और अवसर प्रदान करने वाला होने जा रहा है।

जी–20 में भारत, जर्मनी, जापान, इटली, रूस, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, चीन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, साउदी अरब, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनशिया, तुर्की और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ये विश्व के सभी प्रमुख सशक्त देश हैं, जिसमें भारत की बहुत अहम भूमिका होने

वाली है। भारत ने 2023 के शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश, मारिशस, मिस्र, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और यूई को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

संप्रति, वैश्विक राजनैतिक परिदृश्य काफी उथल–पुथल वाला है। रूस–यूक्रेन युद्ध की चपेट में अमेरिका सहित यूरोपीय देश आ गए हैं। भारत इसमें तटस्थ है और वह चाहता है कि वैश्विक शांति की बाबत इसका हल सौहार्द्रपूर्ण तरीके से ही निकाला जाए। आज भारत के समक्ष बड़ी चुनौती कोविड महामारी है। इसने वैश्विक आपूर्ति को बुरी तरह से प्रभावित किया है। यही नहीं, इसी के चलते विनिर्माण क्षेत्र को गहरा धक्का लगा है। चीन जो मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, अब वह अपनी पकड़ खोता जा रहा है। अनेक पश्चिमी देश अब मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को चीन से निकाल कर भारत सहित अन्य देशों में ले जा रहे हैं अथवा यहां आने के इच्छुक हैं। यह भी भारत के लिए सुनहरा अवसर है कि वह अधिक से अधिक विदेशी निवेश को अपने यहां आकर्षित करने का सार्थक प्रयास करे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही एक लेख लिखकर जिस तरीके से जी–20 की अध्यक्षता को रेखांकित किया है, उससे भारत की भूमिका को लेकर अनेक उम्मीदें जगी हैं। उन्होंने लिखा कि भारत की जी–20 की अध्यक्षता अधिक समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख होगी। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहला कार्य जी 20 के अंदर उस मानसिकता को बदलना है, जो जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और वित्तीय स्थिरता जैसे साझा मुद्दों का सामना करते हुए भी विकासशील देशों को विकसित देशों से अलग करती है। आज विकासशील देशों की भारत से यह अपेक्षा है कि वह जी–20 के अंदर रहते हुए विकसित देशों से वार्ता कर विकसशील और अविकसित देशों की आवाज बनेगा। दूसरी ओर, विकसित देशों को भारत से अपेक्षा है कि वह विश्व में शांति और सद्भाव कायम करने में महती भूमिका निभाएगा।

अंततः मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरीके से वैश्विक मुद्दों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कमजोर अथवा नगण्य हुई है, उस शून्य को भरने का काम जी–20 कर सकता है। जी 20 का नेतृत्व भारत के पास आने के चलते न केवल इसकी भूमिका सशक्त होगी बल्कि भारत विश्व फलक पर एक विश्व गुरु के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा।

लेखक आईएमएस गाजियाबाद में पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय के चेयरपर्सन हैं

ISSN No. 2581-3528

भारत के महत्व को रेखांकित करता जी-20 सम्मेलन

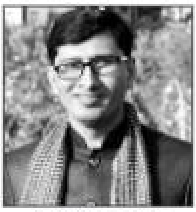

आशीष कुमार

इंडोशिया में संपन्न हुए जी20 देशों के सालाना शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसे भारत के दृष्टिकोण से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दिसंबर 2022 से भारत दुनिया के विकसित देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के इस संगठन की अध्यक्षता करेगा। यह सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में ऐसे समय में हो रहा है जहां पूरी दुनिया में नए वर्ल्ड ऑडर के आकर लेने की बातें चल रही हैं। विश्व शक्ति की बदलती धुरियों को प्रत्यक्ष देखा जा रहा है।

इस समय पूरी दुनिया वैश्विक जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध से उपजे संकट से जूझ रही है। यूरोप को इसबार उर्जा और खाद्य संकट दोनों से जूझना पड़ रहा है। भारत इन संकटों के काल में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को चरितार्थ करते हुए दुनिया की मदद को आगे आया। कोविड काल में विश्व के अनेक देशों को कोविड वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध कराई। यूरोप के खाद्य संकट को दूर करने के लिए अपने देश के खाद्यान्न भंडार निर्यात के लिए खोल दिए। संकट काल में भारत ने वैश्विक नेतृत्व का परिचय दिया।

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही वैश्विक आर्थिक संस्थाओं द्वारा अनुमान लगाए जा रहे है कि 2029 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। सभी जानते हैं कि आर्थिक उन्नति के बिना शक्ति सृजन असंभव है। आर्थिक रूप से मजबूत होते भारत के साथ भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि हो रही है। भारत को विश्व के सभी देश गंभीरता से ले रहे हैं। भारत की बातों को महत्व दिया जा रहा है और अमल किया जा रहा है।

भारत ने वैश्विक उर्जा के संकट को दूर करने के लिए 'एक विश्व एक सूर्य की' परिकल्पना को सबके सामने रखा है। भारत की पहल पर ही 'इंटरनेशनल सोलर एलांएस' की नींव रखी गई थी। भारत का मानना है नवीनीकृत उर्जा के स्वरूप सौर उर्जा को सदपयोग करने के लिए एक 'इंटरनेशनल सोलर ग्रिड' की स्थापना की जानी चाहिए। बाली के जी20 सम्मेलन भारत ने उर्जा संकट के लिए विकसित देशों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन सहित अन्य नेताओं की उपस्थिति में स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की उर्जा सुरक्षा वैश्विक विकास के लिए जरूरी है। और भारत उर्जा की आपूर्ति में किसी भी तरह के प्रतिबंध के खिलाफ है। उन्होंने उर्जा को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले देशों चेताया।

जलवायु परिवर्तनों और कोरोना संकटों के बीच पूरी दुनिया खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का संकट

बना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री ने बाली में कहा कि उपरोक्त संकटों की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह से प्रभावित हुई है। खाद्यान्न संकट के कारण हर देश के गरीब गंभीर तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। भारत ने कोरोना काल में बेहतर तरीके काम किया। गरीब और जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया। भारत के कोविड प्रबंधन की सराहना वैश्विक संस्थानों द्वारा की गई।

यूक्रेन–रूस युद्ध की छाया में हुए इस सम्मेलन में, जिसमें रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन अनुपस्थित रहे। मोदी ने दोहराया कि संघर्ष विराम और कूटनीति के माध्यम से ही समाधान निकाला जा सकता है। यूएनओ में सांगठनिक बदलाव की बात भारत लगातार करता आ रहा है। इसी क्रम में भारत ने जी20 सम्मेलन में भी इस मुददे को भी प्रमुखता के साथ उठाया। भारत के अनुसार यूएनओ का मौजूदा स्वरूप विश्व में शांति कायम रखने में असक्षम है। भारत का मानना है कि यूएनओ का वर्तमान स्वरूप सन् 1945 में स्थापित हुआ था। उसके बाद से विश्व में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। भारत को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। भारत जैसे महत्वूपर्ण और शक्तिशाली राष्ट्र की स्थायी भूमिका के बिना यूएनओ की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठना लाजिमी है। रूस–यूक्रेन युद्ध के दौरान भी यूएनओ की सार्थकता पर सवाल उठ रहे हैं। है। यूएनओ जैसी बहुपक्षीय संस्था निष्फल साबित हुई हैं। ऐसे में जी20 जैसी प्रासंगिकता बढ़ गई है।

प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में रह रहे भारतवंशियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में सामने भारत के विकास की कहानी जिस प्रभावी ढंग से रख रहे हैं उस ओर दुनिया का ध्यान जाना स्वाभाविक है। इस बीच प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन सहित जी20 के कई नेताओं से भी मुलाकात की।

भारत करेगा 18 वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता : 18 वाँ जी20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होना है। जिसकी अध्यक्षता भारत ने दिसंबर 2022 में ग्रहण की। भारत एक वर्ष के लिए जी20 का अध्यक्ष रहेगा। भारत जी20 के अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा।

ट्रोइका का गठन : अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील के साथ मिलकर ट्रोइका का गठन करेंगे। यह पहली बार होगा कि ट्रोइका में विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। ट्रोइका में वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष शामिल रहते हैं।

जी20 का उददेश्य और प्राथमिकताएं : जी20 का गठन का गठन वर्ष 1999 के अंत में वित्तीय संकट की दौरान किया गया था। जी20 देशों में विश्व की 60 फीसदी आबादी, जीडीपी का 80 फीसदी और वैश्विक व्यापार का 75 फीसदी सम्मिलित है। जी20 की प्राथमिकताओं में समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास सम्मिलित है।

जी20 के सदस्य : जी20 समूह में भारत, अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं।

(लेखक मीडियाविद हैं)

ISSN No. 2581-3528

मीठी यादों में बसा एक लाल

नरेन्द्र भदौरिया

इतना बड़ा पाँव और किसी का क्यों नहीं जितना शिक्षक महावीर प्रसाद विद्यार्थी का था। ऐसी पीड़ा भरी टीस के साथ उधार के एक खेत में एक बड़े मनीषी की 103 वीं जयन्ती मनायी गयी। जिसने सभी के मन को रुला दिया। एक सच्चे गुरु थे महावीर प्रसाद विद्यार्थी। उन्नाव के टेढ़ा गाँव के एक विद्यालय में जीवन पर्यन्त रहे। कहते हैं वहाँ उप प्राचार्य थे। सच तो यही है कि विद्यार्थी जी उस विद्यालय के प्राण थे। उनसे तब भी ईर्ष्या करने वाले लोग थे आज भी हैं। ईर्ष्या का कारण बड़ा स्पष्ट था कि वह हर विषय में निष्णात थे। वैसे तो चार विषयों में परास्नातक थे। हिन्दी, अंग्रेजी में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान रहा था। स्वर्ण पदक के अधिकारी बने पर पदक लेने को किसी ने गुहारा ही नहीं। संस्कृत, भूगोल में भी परास्नातक थे। इन विषयों में सर्वोच्चता में दूसरे नम्बर पर रहे। सबसे अचरज की बात यह कि हाई स्कूल से लेकर परास्नातक तक की किसी परीक्षा के लिए उन्होंने स्कूल, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर पढ़ाई नहीं की थी। हर बार स्वयं की पढ़ाई से चमत्कार किया। ऐसे महामानव के साथ टेढ़ा में बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा हुआ। पर यह सब अलग रखकर देखिये कि यह मानव वास्तव में कितना गुणी था।

महावीर प्रसाद 23 दिसम्बर 1920 में जन्मे थे। सुन्दारा देवी माँ थीं। पिता का नाम था शिव दुलारे पटेल। टेढ़ा ही पैतृक गाँव था। महारानी नाम की गृहिणी इनकी जीवन संगिनी थीं। कोई सन्तति नहीं हुई थी। 1941 से 1949 तक प्राथमिक विद्यालय तंत्र से सम्बद्ध शिक्षक रहे। बाद में हुबलाल इण्टर कालेज से जुड़े और अन्त तक वहीं रहे। मात्र 52 वर्ष का जीवन काल रहा। 1972 की 22 मई को प्राणान्त हो गया। इस अवधि में कई और परीक्षाएं दीं। सभी में चमत्कार किया। पीएचडी के लिए शोध ग्रन्थ लिखा और जमा भी कर दिया था। एक ओर इनके गाइड मर गये तो दूसरी त्रासद बात यह कि इनके शोध को लेकर खिलवाड़ हो गया। इनसे प्रतीक्षा करने को कहा गया। जिसकी अवधि कई बार बढ़ती रही। इस बीच अनहोनी ने महावीर प्रसाद के प्राण हर लिये। अनायास इनका जाना इनके शिष्यों को वज्रपात सा लगा।

महावीर प्रसाद एक सन्त या ऋषि सदृश थे। ऐसे विकट स्वाध्यायी थे कि विद्यालयों में प्रचलित प्रत्येक विषय के पण्डित थे। सभी विषयों के विद्यार्थी ही नहीं शिक्षक भी उनसे विद्या अध्ययन के मन्त्र सीखते थे। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में सिद्धस्थ थे। वाणी के अनुशासन पर बहुत ध्यान देते। उर्दू समेत सभी भाषाओं के शब्दों के उच्चारण को हल्के में लेने वालों को बड़ी सरलता से समझाते। वह कहा करते किसी भाषा के शब्दों का उच्चारण कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। उच्चारण का वैविध्य ही तो भाषा का लावण्य होता है। महावीर प्रसाद तब बहुत दुखी होते जब पढ़े लिखे लोग त्रुटिपूर्ण उच्चारण करके नयी पीढ़ी के छात्रों को दिग्भ्रमित करते। महावीर प्रसाद विद्यार्थी ने व्यक्तिगत परीक्षार्थी के नाते उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10 वीं कक्षा की परीक्षा में सर्वोत्तम अंक अर्जित करके जो कीर्तिमान बनाया था वह अब तक नहीं टूटा। जबकि इस बात को 80 बरस से अधिक हो गये। स्यात विद्यार्थी जी के पदचिह्न ही इतने बड़े रहे होंगे कि उनसे बड़े पाँवों वाले लोग ही अब नहीं होते।

महावीर प्रसाद विद्यार्थी

परास्नातक भूगोल की प्रैक्टिकल परीक्षा की कापी देखते हुए यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उन पर विफर गया। वह बोला कि तुमने तो अपनी कॉपी पर पुस्तक से काटकर चित्र सजा लिये हैं। विद्यार्थी जी के आग्रह पर प्रोफेसर ने आँखें टिकाकर देखा तो लज्जित होकर कहा–तुम जैसे छात्र कहाँ मिलते हैं। वास्तव में सारे चित्र विद्यार्थी जी ने स्वयं बनाकर उनमें रंग भरे थे। जिन्हें देखकर वह चकित हो उठा था।

अंग्रेजी की मैखिक परीक्षा देते समय एक प्रोफेसर से विद्यार्थी जी ने एक शब्द के त्रुटिपूर्ण उच्चारण पर विनम्र आपत्ति की तो पहले तो वह अड़ गया कि वही सही है फिर बड़ी विनम्रता से विद्यार्थी जी से क्षमा मांगी थी। विभिन्न भाषाओं के शाब्दिक प्रयोग और उच्चारण की त्रुटियों पर वह बहुत टोकते। कहते भाषा की गरिमा को मत बिगाड़ो। यथार्थ के प्रति आग्रही विद्यार्थी जी सच बोलने को ईश्वर के भजन की

ISSN No. 2581-3528

तरह पवित्र मानते। सच बोलने से परमात्मा ही नहीं स्वयं की आत्मा को तुष्टि मिलती है। यह विद्यार्थी जी के आचरण का मूल मन्त्र था।

ऐसे तापस शिक्षक की 103 वीं जयन्ती मनाने के लिए टेढ़ा में एक रिटायर्ड फौजी किसान को तब अपना खेत देना पड़ा जब उनके समर्थकों को उस विद्यालय के प्रबन्ध तन्त्र ने मना कर दिया जहाँ विद्यार्थी जी ने अन्तिम सांस तक काम किया था। विद्यार्थी जी के पैतृक खेत किसी ने बेच डाले। नन्हीं सी उनकी एक मूर्ति जिस खेत में उनके कुछ शिष्यों और समर्थकों ने लगायी है वही खेत फौजी शिव कुमार ने खरीदा है। फौजी ने बड़ी उदारता से आश्वस्त किया है कि वह विद्यार्थी जी की मूर्ति को अपनी ओर से उखाड़ कर नहीं फेकेंगे। उनके शिष्य जब चाहें उसे अन्यत्र ले जा सकते हैं। आगे क्या होगा यह प्रश्न चिह्न अभी बना रहेगा। इसी खेत के एक कोने में लगी मूर्ति पर 23 दिसम्बर को गेंदे की कुछ मालाएं आड़ी तिरछी डाली गयी थीं। कुछ कुर्सियां टेण्ट के भीतर थीं तो कुछ बाहर। जो माननीय लगे वह भीतर बैठे। शेष को बाहर बिठाया गया। सभी के मानस में विद्यार्थी जी की गहरी छाप थी। उनके कई शिष्य कितनी तडप से आये थे यह आभास इसी बात से हुआ कि बैशाखी, बेंत और वाकर के सहारे ही नहीं कंधों का आश्रय लेकर भी लोग इस खेत में हो रही जयन्ती सभा तक पहुँचे। सभी के मन इस बात से बहुत बोझिल थे कि विद्यार्थी जी का पीएचडी के लिए दिया गया शोध ग्रन्थ क्यों चोरी हो गया। उन्हें मरणोपरान्त ही सही इसे सम्मान के भाव से दिया जाता तो किसी का क्या बिगड़ जाता। ऐसी आशंका हवा में तैरती रही कि किसी ने चोरी से उसी ग्रन्थ पर पीएचडी ले ली है।

महावीर प्रसाद जाति सूचक शब्द से अपनी पहचान नहीं चाहते थे। इसीलिए विद्यार्थी उपनाम अपनाया था। उनके शिष्य शिवाधार अब बिना वाकर के नहीं चल पाते। वह कहते हैं कि विद्यार्थी जी मन्त्रदृष्टा ऋषियों की भाँति प्रचण्ड बौद्धिक क्षमता के व्यक्ति थे। उनकी आंखें इस बात पर डबडबायी आयीं कि उनकी जयन्ती के लिए हम एक उधार के खेत में बैठे हैं। यह फौजी भी इतनी उदारता नहीं दर्शाता तो मूर्ति लेकर कहाँ भागते फिरते।

डॉक्टर जगत बहादुर सिंह बैसवारा की धरती के लाल हैं। कई भाषाओं के मर्मज्ञ हैं। जितने विनयी उतने ही सहृदय हैं। श्रीरामसिंह जी की तरह तज्ञ मानव हैं। इन दोनों के मन की बड़ी टीस है कि महावीर सिंह को समाज ने वह स्वीकृति अब तक क्यों नहीं दी जिसके वह अधिकारी हैं। यह अपेक्षा डॉक्टर राम नरेश यादव, कानपुर के डीआईओएस मुन्नीलाल, एमएलसी राज बहादुर सिंह, लेखक वीडी सिंह, राम अवतार कुशवाहा, भारत सिंह, कवि नरेन्द्र, गौरी सिंह, गोपीचन्द्र त्रिपाठी, पूर्णेन्द्र शौर्य, विभूति सिंह पटेल को भी है कि एक दिव्य प्रतिभा को पहचानने और उचित सम्मान देने में चूक हो रही है। विचित्रता है कि अनेक सरकारी संस्थान भी इहलोक की अतिमानवीय प्रतिभाओं को स्वीकारते हुए लजाते से भागते दिखते हैं।

(लेखक राष्ट्रवादी विचारक एवं लेखक हैं)

ISSN No. 2581-3528

वर्ष 2023 आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए एक सुनहरा वर्ष साबित होगा

प्रहलाद सबनानी

अब तो वैश्विक स्तर पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, यूरोपीयन यूनियन, एशियाई विकास बैंक, आदि ने वर्ष 2023 में भारत को पूरे विश्व में सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति करने वाला देश बने रहने की सम्भावना पूर्व में ही व्यक्त कर दी है और यह पूर्वानुमान विश्व के लगभग समस्त विकसित देशों के आर्थिक संकटों में घिरे रहने के बीच लगाया गया है। हालांकि इस बीच, हाल ही के समय में, चीन एवं कुछ अन्य देशों में कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है तथा यूक्रेन एवं रूस के बीच युद्ध समाप्त होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं परंतु फिर भी इन समस्त विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत किस प्रकार पूरे विश्व में एक चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रहा है।

दरअसल, यह सब भारत सरकार द्वारा समय समय पर लिए गए कई आर्थिक निर्णयों के चलते सम्भव होता दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व में आज ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें वर्ष 2015 के बाद से 50 करोड़ के आसपास बैंक खाते खोले गए हों। एक अनुमान के अनुसार, भारतीय बैंकों में खोले गए उक्त खातों में से 90 प्रतिशत से अधिक खातों में निरंतर व्यवहार किए जा रहे हैं। देश की एक बहुत बड़ी आबादी को बैंकों के साथ जोड़कर उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर बनाया गया है। साथ ही, भारत में ही वर्ष 2015 के बाद से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3 करोड़ नए मकान केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों को सौंपे गए हैं एवं अभी भी सौंपे जा रहे हैं। इसी प्रकार "हर घर में नल" एक विशेष योजना के अंतर्गत 2.43 करोड़ परिवारों को नल के नए कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना जैसी महामारी से अपने नागरिकों को बचाने के उद्देश्य से भारत में अपना स्वयं का स्वदेशी टीका विकसित कर, 220 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके मुफ्त ही अपने नागरिकों को लगाए गए हैं, जो कि पूरे विश्व में एक रिकार्ड है। इसके चलते ही भारत में कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सका है। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के बीच प्रारम्भ की गई गरीब अन्न योजना, जिसके अंतर्गत दिसम्बर 2023 तक, 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता रहेगा। भारत में लगभग 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार लगभग 50 करोड़ नागरिकों को इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। आप जरा उक्तवर्णित आंकड़ों पर गौर करें, आज पूरा विश्व ही आश्चर्य चकित है कि भारत में केंद्र सरकार किस प्रकार इतने बड़े स्केल पर भारत की जनता के हितार्थ आर्थिक निर्णय ले रही है एवं इस संबंध में अपने लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करती जा रही है। यहां पर उक्त तो केवल कुछ उदाहरण दिए गए हैं वरना वर्ष 2014 के बाद से इस प्रकार के अनेकों निर्णय कई क्षेत्रों में लिए गए हैं जिनसे पूरा विश्व ही आज हक्का बक्का हो गया है।

वैश्विक स्तर पर भारत ने अभी हाल ही में कई क्षेत्रों में अपनी अगुवाई सिद्ध की है। सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तो पूरे विश्व में एक तरह से भारतीय मूल के इंजीनियरों द्वारा चलाया जा रहा है। अमेरिका की सिलिकोन वैली इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत में डिजिटल प्लेटफोर्म को जिस प्रकार से शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र एवं दूर दराज के इलाकों तक फैलाया गया है, इसको देखकर पूरा विश्व ही आज आश्चर्यचकित है एवं इस क्षेत्र में विकसित देश भी आज भारत से मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। फार्मा उद्योग एक और ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत आज पूरे विश्व के लिए एक फार्मेसी हब बन गया है। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने विश्व के लगभग समस्त देशों को दवाईयां उपलब्ध करवाईं। आज पूरे विश्व में सबसे अधिक दवाईयों एवं टीकों का निर्माण भारत में हो रहा है एवं भारत ही विभिन्न देशों को दवाईयां एवं टीके उपलब्ध करवा रहा है। हाल ही के समय में भारत ने औटोमोबाइल एवं मोबाइल के उत्पादन के क्षेत्र में भी द्रुत गति से विकास किया है। भारत सरकार द्वारा 23 प्रकार के विभिन्न उद्योगों के लिए लागू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ अब इन दो उद्योगों के साथ ही कुछ अन्य उद्योगों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार करने की दृष्टि से भी फोसिल फ़्यूल (डीजल, पेट्रोल एवं कोयला) के उपयोग को कम कर नॉन–फोसिल फ़्यूल (सूर्य की रोशनी एवं वायु से निर्मित फ़्यूल) के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस संदर्भ में भारत ने अपनी अगुवाई में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 70 देशों को मिलाकर एक समूह भी बनाया है जो कि इन सदस्य देशों में नॉन–फोसिल फ़्यूल के उपयोग को बढ़ावा देगा। इससे पूरे विश्व में डीजल, पेट्रोल एवं कोयले पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी।

भारत अभी तक सुरक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः आयातित उत्पादों पर ही निर्भर रहता था। छोटे से छोटा उत्पाद भी विकसित देशों से आयात किया जाता रहा है। परंतु हाल ही के समय में भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में आत्म–निर्भरता हासिल करने की ओर अपने कदम बढ़ा दिये हैं। बल्कि, भारत आज सुरक्षा के कई उपकरणों, मिसाईल एवं हवाई जहाज जैसे उच्च स्तर के उत्पादों सहित, का निर्यात भी करने लगा है।

इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी भारत ने अकल्पनीय विकास किया है। अभी हाल ही में रूस एवं यूक्रेन के बीच छिड़े जंग के कारण कई देशों को भारत ने ही गेहूं जैसे खाद्य पदार्थों का निर्यात कर इन देशों के नागरिकों की भूख मिटाने में सफलता पाई। आज भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश में आज खाद्यान (गेहूं एवं धान) उत्पादों से अधिक दलहन, तिलहन, फल एवं सब्ज़ियों जैसे उत्पादों का अधिक उत्पादन हो रहा है जिससे किसानों की आय में तेज गति से वृद्धि हो रही है एवं जिसके कारण भारत के ग्रामीण इलाकों में गरीबी भी तेजी से कम हो रही है, इसकी सराहना तो विश्व बैंक एवं आईएमएफ ने भी अपने प्रतिवेदनों में की है।

भारत ने हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात एवं आस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं एवं ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीयन यूनियन देशों के साथ भी इस तरह के द्विपक्षीय समझौते शीघ्र ही सम्पन्न किये जा रहे हैं। हाल ही में सम्पन्न किए गए इन समझौतों का प्रभाव भी वर्ष 2023 में पूर्ण तौर पर दिखाई देगा। यूनाइटेड अरब अमीरात तो सम्भावना व्यक्त कर रहा है कि शीघ्र ही उसका भारत के साथ विदेशी व्यापार 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू सकता है। इस प्रकार की उम्मीद आस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन जैसे देश भी कर रहे हैं। अमेरिका एवं चीन से तो पहिले से ही भारत का व्यापार 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है।

भारत को आर्थिक क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अभी हाल ही में एक और

मौका मिला है। भारत को जी–20 देशों की अध्यक्षता एक वर्ष के लिए सौंपी गई है। जी–20 देशों के समूह की अध्यक्षता भारत को मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पूरे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत हिस्सा इस समूह के देशों से आता है। विश्व में होने वाले विदेशी व्यापार का 78 प्रतिशत हिस्सा इन देशों के बीच से निकलता है। विश्व के लगभग 90 प्रतिशत पैटेंट एवं ट्रेडमार्क इसी जी–20 समूह के देशों के रजिस्टर होते हैं, अर्थात, विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतम नवोन्मेश भी इसी समूह के देशों में हो रहा है। साथ ही, विश्व के दो तिहाई से अधिक आबादी भी इसी समूह के देशों में पाई जाती है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि जी–20 समूह के देशों की आर्थिक नीतियों एवं विदेशी व्यापार को यदि प्रभावित करने में भारत सफल रहता है तो भारत आने वाले समय में पूरे विश्व के आर्थिक पटल पर शीघ्र ही एक दैदीप्यमान सितारे के रूप में चमकेगा। जिसकी सम्भावना विश्व के विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा अभी से की जा रही है। वर्ष 2023 में जी–20 देशों के समूह की विभिन्न प्रकार की लगभग 200 बैठकों का आयोजन भारत में विभिन्न शहरों में किया जाएगा। भारत में आयोजित होने वाली इन अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठकों के लिए विभिन्न राज्यों को अपने शहरों में आधारभूत संरचना का विकास करना होगा जिससे इन शहरों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

आज पूरा विश्व ही अपनी आर्थिक समस्याओं जैसे, मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, तेजी से बढ़ रही आय की असमानता, वित्तीय अस्थिरिता, लगातार बढ़ रहे ऋण, बजटीय असंतुलन आदि को हल करने के उद्देश्य से भारत की ओर बहुत आशा भरी नजरों से देख रहा है। प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था पर यदि नजर डालें तो ध्यान में आता है कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी एवं उस समय पर भारत में अर्थव्यवस्था को धर्म के आधार पर चलाया जाता था जिसके कारण उक्त वर्णित किसी भी प्रकार की समस्या पाए जाने का जिक्र हमारे भारतीय इतिहास में नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों का वर्णन भारत के शास्त्रों में मिलता है, जिनके अनुसार उस समय पर अर्थव्यवस्था का संचालन होता था एवं अर्थ से सम्बंधित समस्याएं लगभग नहीं के बराबर रहती थी। इस प्रकार अब समय आ गया है जब भारत को धर्म पर आधारित आर्थिक निर्णयों को लेकर पूरे विश्व को राह दिखानी चाहिए ताकि पूरे विश्व में व्याप्त आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर किया जा सके।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक पद से सेवा निवृत्त हैं)

ISSN No. 2581-3528

हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उपासक - मालवीय जी

मृत्युंजय दीक्षित

आधुनिक भारत में प्रथम शिक्षा नीति के जनक, शिक्षा के विशाल केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, सांस्कृतिक नवजागरण स्वदेशी एवं हिंदी आंदोलनों के प्रवर्तक राष्ट्रभक्त महान समाज सुधारक भारतीय काया में पुनः नयी चेतना एवं ऊर्जा का संचार करने वाले महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसम्बर 1861 को हुआ था। मालवीय जी के पिता पण्डित ब्रजनाथ कथा, प्रवचन और पौरोहित्य से ही अपने परिवार का पालन– पोषण करते थे। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करके मालवीय जी ने संस्कृत व अंग्रेजी पढ़ी। मालवीय जी युवावस्था में अंग्रेजी तथा संस्कृत दोनों ही भाषाओं में धाराप्रवाह बोलते थे। महामना मदन मोहन मालवीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। खेलकूद, व्यायाम,कुश्ती, बांसुरी एवं सितार वादन में उनकी रुचि थी। बाल जीवन में ही एक भाषण– दल बनाया था जो चौराहों पर तथा मेलों, सभाओं में विभिन्न विषयों पर भाषण दिया करता था। कवि और साहित्यकार की प्रतिभा भी विद्यमान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि मंडली में भी जुड़े हुए थे।

स्नातक करने के बाद मालवीय जी ने अध्यापक की नौकरी की तथा बाद में वकालत भी की। उनकी वकालत की विशेषता थी– गरीबों तथा सार्वजनिक हित के मामलों में कोई फीस न लेना, जिसमें झूठ बोलना पड़े ऐसा केस न लेना। महामना ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया। जुलाई 1887 से जून 1889 तक हिंदी दैनिक हिन्दोस्थान (कालांकर) के मुख्य संपादक, जुलाई 1889 से 1992 तक अंग्रेजी पत्र "इण्डियन यूनियन" के सह संपादक और 1907 में साप्ताहिक अभ्युदय 1909 में अंग्रेजी दैनिक लीडर 1910 में हिंदी पाक्षिक मर्यादा एवं 1933 में हिंदी साप्ताहिक सनातन धर्म के संस्थापक तथा कुछ वर्षों तक इन सभी पत्रों के संपादक रहे। मालवीय जी 1924 से 1940 तक हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के चेयरमैन रहे। मालवीय जी ने 1908 में अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन, प्रयाग के अध्यक्ष पद से समाचार पत्रों की स्वतंता का हनन करने वाले सरकारी प्रेस एक्ट तथा न्यूज पेपर एक्ट की कड़ी आलोचना की थी। सन 1910 में मालवीय जी ने प्रान्तीय कौंसिल में सरकारी प्रेस विधेयक का कड़ा विरोध किया। जनचेतना एवं जनआंदोलन की लहर जगाने में महामना की पत्रकारिता ने एक बड़ी भूमिका निभायी थी। उनके लिये पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं अपितु एक धर्म था। वे पत्रकारिता को एक कला मानते थे।

हिंदू धर्म व समाज पर जब भी कोई संकट आता तो वे तुरंत सक्रिय हो जाते थे। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के लिए 24 घंटे कार्यरत रहते थे। उन्होने 10 अक्टूबर 1910 को काशी में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की और अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने सभी से हिंदी सीखने का आह्वान किया। 19 अप्रैल 1919 को बम्बई में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मालवीय जी ने देवनागरी लिपि में लिखी गयी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्रदान करने पर जोर दिया। मालवीय जी भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन, साहित्य, संस्कृति और अन्य सुविधाओं के साथ– साथ अर्वाचीन नीतिशास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, विधि विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन आवश्यक समझते थे। हिंदी की सेवा और गोरक्षा में उनके प्राण बसते थे।

उन्होने लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद के साथ मिलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी। वे 1923, 24 और 36 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। जबकि 1909, 18, 32, 33 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वे महान समाजसेवी भी थे। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत प्रयास किये। महिलाओं में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं खुलवायीं। उन्होनें अपने जीवनकाल में ही व्यायामशाला, गौशाला और मंदिर भी बनवाये। हर हिंदू के प्रति प्रेम होने के कारण उन्होनें हजारों हरिजन बंधुओं को ऊँ नमः शिवाय और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी।

मालवीय जी ने नवम्बर सन 1889 में भारती भवन नाम से पुस्तकालय स्थापित करवाया। जिसका उद्देश्य हिंदी और संस्कृत पुस्तकों का संग्रह और अध्ययन था। मालवीय जी ने हिंदू विद्यार्थियों के रहने के लिए एक छात्रावास के निमित्त प्रांतों में घूम कर धन एकत्र किया। वे जीवन पर्यंत समाजसेवा में रत रहे ।

अगस्त 1946 में जब मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही के नाम पर पूर्वोत्तर भारत में कत्लेआम किया तो मालवीय जी बीमार थे। वहां हिंदू नारियों पर अत्याचारों को सुनकर वे रो पड़े। इसी अवस्था में 12 नवंबर 1946 को उनका देहान्त हुआ।

आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता -भारतरत्न श्रद्धेय अटल जी

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी एक कुशल राजनीतिज्ञ, सहृदय व्यक्तित्व के धनी, भावपूर्ण कवि और प्रख्यात पत्रकार थे जिनके मन में सदैव देश ही सर्वोपरि रहता था। आज भारत जिस तेज गति से मिसाइलों के परीक्षणों के द्वारा अपनी सुरक्षा को अभेद्य बना रहा है और भारत के शत्रु इसकी बढ़ती सैन्य शक्ति व आत्मनिर्भर हो रही रक्षा प्रणाली से भयभीत हो रहे हैं वह अटल जी की ही सरकार का प्रारंभ किया हुआ कार्य है जिसे मोदी जी पूरा कर रहे हैं।

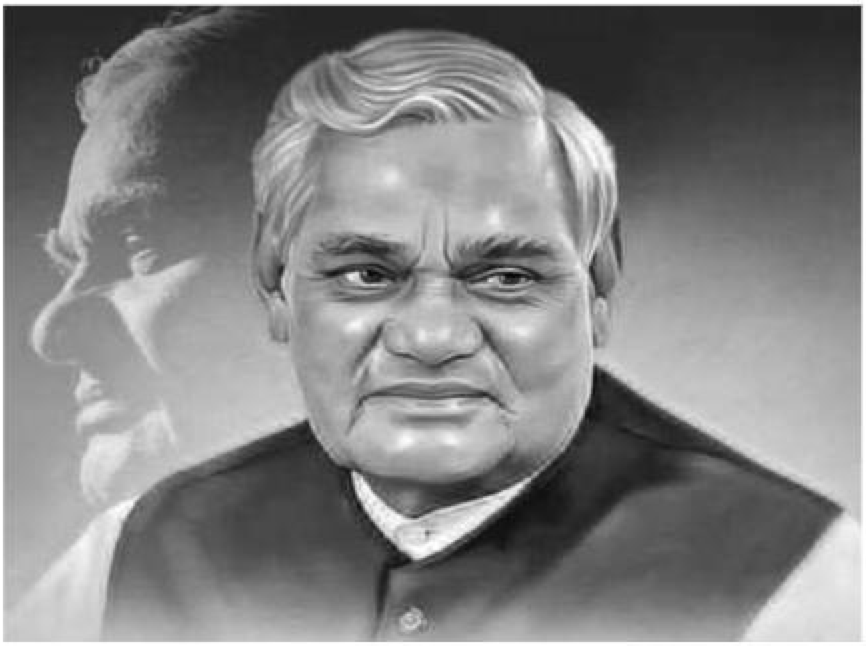

अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जिन परियोजनाओं पर काम किया गया वही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में धरातल पर उतर रही हैं। इनमे से अधिकांश बीच में आई सरकार ने ठन्डे बस्ते में डाल दी थीं। अटल जी का एक सपना अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में पूरा हो रहा है, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद–370 और 35–ए का समापन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में आगे बढ़ते कार्यों में सर्वत्र अटल जी की ही छाप है।

अटल जी का जन्म 25 दिसम्बर 1926 को शिंदे की छावनी (मध्य प्रदेश) में प्राइमरी स्कूल अध्यापक स्वर्गीय पंडित कृष्ण बिहारी बाजपेयी के घर पर हुआ।उनकी माता का नाम श्रीमती कृष्णा देवी था जो कि धर्मपरायण महिला थीं। अटल जी का पूरा परिवार संघ के प्रति निष्ठावान था। वह आठ वर्ष की आयु में ही संघ के संपर्क में आ गये और विद्यार्थी जीवन में ही संघ से प्रेरित होकर मन में ठान लिया था कि वे देश के लिये जियेंगे और देश लिये ही मरेंगे। अटल जी की शिक्षा दीक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज और कानपुर के डी ए वी कालेज में सम्पन्न हुई। स्नातक और उसके उपरांत राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की परीक्षाएं अटल जी ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की ।इसके बाद अपने पिता के साथ ही एल एल बी किया। छात्र जीवन में छात्र राजनीति में

सक्रिय रहकर वे विक्टोरिया कॉलेज छात्र संघ के महामंत्री ,ग्वालियर छात्र संघ के अध्यक्ष एवं आर्य कुमार सभा के महामंत्री बने।

अटल जी को मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त था जिससे वे छात्र जीवन में ही वाद विवाद और काव्य पाठ आदि में भाग लेकर लोकप्रिय हो गए थे। वह लम्बे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन तथा स्वदेश जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे। उन्होंने 1946 में ही अपना जीवन संघ को समर्पित कर दिया था उन्होंने काफी समय तक पूर्णकालिक प्रचारक के रूप मे कार्य किया। अटल जी कहा करते थे कि भारत का प्रत्येक कण स्वर्ग से भी अधिक पवित्र है तथा महान तीर्थ है। उनका कहना था कि हमारे एकमात्र देवी देवता हमारे देशवासी हैं। उनकी पूजा अर्चना ही सच्ची मानवता है। हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल स्रोत हमारा धर्म है। निष्काम कर्मयोगी अटल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे।

अटल जी का राजनैतिक जीवन संघर्ष पूर्ण रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को उखाड़ फेकने में अटल जी ने महती भूमिका निभाई। अटल जी व संघ ने आपातकाल के विरुद्ध अनथक संघर्ष किया जिसके परिणामस्वरूप ही मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी जिसमें अटल जी विदेश मंत्री बने। वह देश के ऐसे पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया।

अटल जी तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने। पहले 13 दिन, फिर 13 माह व फिर पूरे सत्र के लिए। अटल जी की सरकार में कई ऐतिहासिक कदम उठाये गये थे जिनकी गूंज आज भी सुनायी दे रही है। अटल जी सरकार ने वैश्विक दबाव को नजरअंदाज करते हुए परमाणु परीक्षण किये जिसके करण कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध भी लगाये लेकिन वह किसी दबाव में नहीं झुके। अटल जी ने पाकिस्तान के साथ मैत्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाहौर से बस यात्रा भी की लेकिन इसके बदले में भारत को पाकिस्तान के विश्वासघात का सामना करना पड़ा लेकिन कारगिल की पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया और अटल सरकार की नेतृत्व क्षमता उजागर हुयी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अटल जी सरकार में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम शुरू हुए। सौ वर्ष पुराना कावेरी विवाद सुलझाया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना प्रारंभ हुई।

अटल जी को अपने राजनीतिक जीवन में कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिसमें 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार एवं भारतरत्न प्रमुख हैं। उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय ने 1993 में डी लिट की मानद उपाधि भी प्रदान की। 2015 में बांग्लादेश की ओर से फ्रेंडस ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अटल जी एक ऐसे राजनेता थे जिनका सम्मान विरोधी का विचारधारा के लोग भी करते थे।

अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जिन परियोजनाओं पर काम किया गया वही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में धरातल पर उतर रही हैं। इनमे से अधिकांश बीच में आई सरकार ने ठन्डे बस्ते में डाल दी थीं। अटल जी का एक सपना अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में पूरा हो रहा है, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद-370 और 35-ए का समापन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में आगे बढ़ते कार्यों में सर्वत्र अटल जी की ही छाप है।

अटल जी ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ को अंतरराष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया। अटल जी लखनऊ से पांच बार सांसद रहे जिसमें तीन बार प्रधानमंत्री बने। अटल जी लखनऊ में 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में सांसद बने। 1991 में उन्होंने कांग्रेस के रंजीत सिंह को हराया, 19996 में उन्होंने सपा के राज बब्बर को, 1998 में सपा के मुजफ्फर अली को 1999 में कांग्रेस के डा कर्ण सिंह को और 2004 में सपा की मधु गुप्ता को दो लाख मतों के भारी अंतर से पराजित करने का रिकार्ड बना दिया। लखनऊ में अटल जी को पराजित करने के लिये विपक्ष ने हर चुनाव में नये तरीके आजमाए लेकिन हर बार उन्हें पराजय ही मिली।

अटल जी ने लखनऊ को एक माडल के रूप में विकसित किया।वह नये और पुराने शहर की बराबर चिंता किया करते थे। अटल जी को लखनऊ की तेजी से बढ़ रही आबादी का अनुमान था। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गोमती नगर रेलवे स्टेशन को चारबाग जैसी सुविधाओं के साथ बनाने का प्रस्ताव तैयार कराया। फैजाबाद रोड से अमौसी तक अमर शहीद पथ के निर्माण की कल्पना उन्हीं की देन है। लखनऊ–कानुपर हाईवे का चौड़ीकरण लखनऊ – हरदोई का चौड़ीकरण, दीन दयाल स्मृतिका, निशातगंज फ्लाईओवर, कल्याण मंडप भी अटल जी की ही देन है। अटल जी ने ही साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर बनवाया तथा टिकैतराय तालाब और कुड़ियाघाट का जीर्णोद्धार कराया। अटल जी की ही पहल पर पुराने लखनऊ की संकरी गलियों में गहरे गड्ढों वाली पतली सीवर लाइन की बुनियाद पड़ी। बाद में पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम की योजना बनी। लखनऊ मेट्रो की कल्पना भी उन्हीं के कार्यकाल में आयी थी। राजधानीलखनऊ अटल जी की राजनीतिक कर्मभूमि थी। अटल जी ने 25 अप्रैल 2007 को कपूरथला चौराहे पर भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में अंतिम बार एक चुनावी सभा को संबोधित किया था।

अटल जी के जीवन में "सादा जीवन उच्च विचार" के मंत्र का वास्तविक स्वरूप दिखता है।

(लेखक स्तम्भकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय सोच से ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है

अदिति अग्रवाल

पिपिछले दस वर्षों की भारत की जीडीपी (gross domestic production) की बात करें तो 2012–13 में ग्रोथ रेट 5.46 फीसदी थी तो 2021–22 में यह 8.95 प्रतिशत पहुंच गई। कोरोना काल की गणना करना न्यायसंगत नहीं है। हाँ अगर भारत का वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व धैर्यवान नही होता तो भारत की अर्थव्यवस्था भी कोरोना काल के बाद एकदम पटरी पर आना असम्भव बात होती। किसी देश की अर्थव्यवस्था की गणना का आधार आज जीडीपी है। हालांकि जीडीपी विभिन्न समयगत कारणों से प्रभावित होकर कम ज्यादा होती रहती है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना में किसी भी देश की व्यापार, कृषि और सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसलिये भारत के प्रत्येक नागरिक की भूमिका राष्ट्रीय सोच के साथ काम करने वाली बननी चाहिय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि साल 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन (5 लाख करोड़) डॉलर की बना देंगे और भारत सरकार इस दिशा में तेजी से काम भी कर रही है। पूरे एशिया में भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते मूल्यांकन को देखा जा रहा है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण शायद भारत को 5 टिलियन डॉलर तक अपनी अर्थव्यवस्था पहुंचाने में शायद कुछ समय और लग जाये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।

लोगों की सोच रहती है कि देश की जीडीपी बढ़ानी है तो यह तो कॉरपोरेट घरानों का काम है। ऐसा नही है, छोटे से छोटे व्यापारी, किसान और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के दम पर ही अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। जीडीपी की गणना में उनका योगदान बड़ा महत्व रखता है।

भारत की अर्थव्यवस्था लगातार वैश्विक स्तर पर कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पिछले 2021 के अंत मे यह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुये विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी। और आने वाले वर्षो में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया के सामने होगा। ऐसा दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का आकलन कहता है। लेकिन भारत के वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सम्बोधन में बार बार भारत को आत्म निर्भर बनाने की बात पर जोर देते है। क्योंकि उनकी चिंता है कि भारत का निर्यात बढ़ना चाहिय और आयात कम होना चाहिये। वर्ष 2021–22 में भारत के विदेशी व्यापार में मजबूती से सुधार हुआ। भारत 2021–22 के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी वस्तु निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग पर बेहतर तरह से अग्रसर हुआ। कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में 23.2 प्रतिशत बढ़ोतरी भारत ने की। 2021–22 की आर्थिक समीक्षा बताती है कि भारत में मजबूत पूंजी प्रवाह से विदेशी मुद्रा भंडार का तेजी से संचय हुआ है। भारत विश्व के 190 देशों को लगभग 7500 वस्तुएं निर्यात करता है लगभग 140 देशों से 6000 वस्तुए आयात करता है फिर भी आयात की तुलना में निर्यात बहुत कम है और यही कारण है कि भारत को मुद्रा का बड़ा भाग विदेशों को देना पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत के लिये विदेशों को जाने वाली मुद्रा को कम करना होगा जो अपने देश मे उत्पादन बढ़ाने के साथ सेवा क्षेत्र को मजबूत करने से सम्भव होगा।

नवम्बर, 2021 के अन्त में भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। चालू वर्ष के दौरान भारत के विदेशी क्षेत्र का लचीलापन अर्थव्यवस्था में विकास के पुनरुद्धार के लिए अच्छा संकेत है। भारतीयों का रहन सहन का स्तर बढा है, परचेजिंग पावर बढ़ी है। लेकिन अगर कुछ घटा है तो वह है भारत के नागरिकों की राष्ट्रीय सोच। इसलिये भारत को आने वाले समय मे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र की उन्नति की सोच के साथ काम करना होगा।

(लेखिका टेक्निया इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज एफिलिएटेड टू गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी रोहिणी, नई दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है)

ISSN No. 2581-3528

समान नागरिक संहिता पर संसद के गरमाने का औचित्य

प्रमोद भार्गव

समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर संसद का गरमा जाना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच भाजपा सदस्य किरोड़ी लाल मीना ने सामान नागरिक संहिता पर राज्यसभा में निजी विधेयक पेश किया है। भाजपा के ही एक अन्य सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शून्य काल में नोटिस दिया है। इस प्रक्रिया के साथ ही उच्च सदन में स्पष्ट राजनीतिक विभाजन देखने में आया। आखिर जब समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के नीति निर्देषक तत्वों में शामिल है, तो फिर जिम्मेवार लोगों का एतराज क्यों? हालांकि मत विभाजन के जरिए इस विधेयक पर बहस की मंजूरी दे दी गई। हालांकि आजादी के बीते 75 सालों में निजी विधेयकों पर कानून बनने के उदाहरण अपवाद ही हैं। किंतु इसे लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि यह कानून की शक्ल में बदल सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्राथमिकता में होने के साथ वचनबद्धता के रूप में भी सामने आया है। इसे कानूनी रूप देना इसलिए संभव लग रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष के ही सांसदों ने इसे संसद के पटल पर रखा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे भाजपा शासित बड़े राज्य विधान सभाओं के जरिए इसे लागू करने की पहल कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव के दौरान भाजपा ने इसे लागू करने का घोषणा–पत्र में वादा भी किया था। हालांकि यहां उसे पराजय का मुख देखना पड़ा। सब कुल मिलाकर यह संकेत मिल रहा है कि सरकार इसे लागू करने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है।

संविधान में दर्ज नीति–निर्देशक सिद्धांत यही अपेक्षा रखता है कि समान नागरिकता लागू हो। जिससे देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक ही तरह का कानून वजूद में आ जाए, जो सभी धर्मों, संप्रदायों और जातियों पर लागू हो। आदिवासी और घूमंतू जातियां भी इसके दायरे में आएंगी। केंद्र में सत्तारूढ़ राजग सरकार से यह उम्मीद ज्यादा इसलिए है, क्योंकि यह मुद्दा भाजपा के बुनियादी मुद्दों में शामिल है। इसमें सबसे बड़ी चुनौतियां बहुधर्मों के व्यक्तिगत कानून और वे जातीय मान्यताएं हैं, जो विवाह, परिवार, उत्तराधिकार और गोद जैसे अधिकारों को दीर्घकाल से चली आ रही क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को कानूनी स्वरूप देती हैं। इनमें सबसे ज्यादा भेद महिलाओं से बरता जाता है। एक तरह से ये लोक प्रचलित मान्यताएं महिला को समान हक देने से खिलवाड़ करती हैं। लैंगिक भेद भी इनमें स्पष्ट परिलक्षित हैं। मुस्लिमों के विवाह व तलाक कानून महिलाओं की अनदेखी करते हुए पूरी तरह पुरुषों के पक्ष में हैं। ऐसे में इन विरोधाभासी कानूनों के तहत न्यायपालिका को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। अदालत में जब पारिवारिक विवाद आते हैं तो अदालत को देखना पड़ता है कि पक्षकारों का धर्म कौनसा है? और फिर उनके धार्मिक कानून के आधार पर विवाद का निराकरण करती है। इससे व्यक्ति का मानवीय पहलू तो प्रभावित होता ही है, अनुच्छेद 44 की भावना का भी अनादर होता है। दरअसल ब्रिटिश कालीन भारत–1772 में सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े अलग–अलग कानून बने थे, जो आजादी के बाद भी अस्तित्व में हैं। हालांकि अब तीन तलाक खत्म कर दिया गया है।

वैसे तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी मूल्य समानता है, लेकिन बहुलतावादी संस्कृति, पुरातन परंपराएं और धर्मनिरपेक्ष राज्य अंततः कानूनी असमानता को अक्षुण्ण बनाए रखने का काम करते रहे हैं। इसलिए समाज लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकारें तो बदल देता है, लेकिन सरकारों को समान कानूनों के निर्माण में दिक्कतें आती हैं। इस जटिलता को सत्तारूढ़ सरकारें समझती हैं। संविधान के भाग–4 में उल्लेखित राज्य–निर्देषक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद–44 में समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता पर क्रियान्वयन कर सकता है। किंतु यह प्रावधान विरोधाभासी है, क्योंकि संविधान के ही अनुच्छेद–26 में विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने व्यक्तिगत प्रकरणों में ऐसे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो धर्म–सम्मत कानून और लोक में प्रचलित मान्यताओं के हिसाब से मामलों के निराकरण की सुविधा धर्म संस्थाओं को देते हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता की डगर कठिन है। क्योंकि धर्म और मान्यता विशेष कानूनों के स्वरूप में ढ़लते हैं तो धर्म के पीठासीन; मंदिर, मस्जिद और चर्च के मुखिया, अपने अधिकारों को हनन के रूप में देखते हैं।

इस्लाम और ईसाइयत से जुड़े लोग इस परिप्रेक्ष्य में यह आशंका भी व्यक्त करते हैं कि यदि कानूनों में समानता आती है तो इससे बहुसंख्यकों, मसलन हिंदुओं का दबदबा कायम हो जाएगा। जबकि यह परिस्थिति तब निर्मित हो सकती है, जब बहुसंख्यक समुदाय के कानूनों को एकपक्षीय नजरिया अपनाते हुए अल्पसंख्यकों पर थोप दिया जाए। यह पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में कतई संभव नहीं है। विभिन्न पर्सनल कानून बनाए रखने के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि समान कानून उन्हीं समाजों में चल सकता है, जहां एक धर्म के लोग रहते हों? भारत जैसे बहुधर्मी देश में यह व्यवस्था इसलिए मुश्किल है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के मायने हैं कि विभिन्न धर्म के अनुयायियों को उनके धर्म के अनुसार जीवन जीने की छूट हो? इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शासन पद्धति, बहुधार्मिकता और बहुसांस्कृतिकता को बहुलतावादी समाज के अंग माने गए हैं। इस विविधता के अनुसार समान अपराध प्रणाली तो हो सकती है, किंतु

ISSN No. 2581-3528

समान नागरिक संहिता संभव नहीं है ? इस दृष्टि से देश में 'समान दंड प्रक्रिया संहिता' तो बिना किसी विवाद के आजादी के बाद से लागू है, लेकिन समान नागरिकत संहिता के प्रयास अदालत के बार–बार निर्देष के बावजूद संभव नहीं हुए हैं। इसके विपरीत संसद निजी कानूनों को ही मजबूती देती रही है।

अब कई सामाजिक और महिला संगठन अर्से से मुस्लिम पर्सनल लॉ पर पुनर्विचार की जरूरत जता रहे हैं। इसी मांग का परिणाम तीन तलाक का समापन है। मुस्लिमों में बहुविवाह पर रोक की मांग भी उठ रही है। यह अच्छी बात है कि शीर्ष न्यायालय ने भी इस मसले पर बहस और कानून की समीक्षा की जरूरत को अहम् माना है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि खुद मुस्लिम समाज के भीतर पर्सनल लॉ को लेकर बेचैनी बढ़ी है। ऐसे महिला और पुरुष बड़ी संख्या में आगे आए हैं, जो यह मानते हैं कि पर्सनल लॉ में परिवर्तन समय की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस–ये–मुशावरत ने भी अपील की थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमा मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किए जाएं। इस्लाम के अध्येता असगर अली इंजीनियर मानते थे कि भारत में प्रचलित मुस्लिम पर्सनल लॉ दरअसल 'ऐंग्लो मोहम्मडन लॉ' है, जो फिरंगी हुकूमत के दौरान अंग्रेज जजों द्वारा दिए फैसलों पर आधारित है। लिहाजा इसे संविधान की कसौटी पर परखने की जरूरत है।

दरअसल देश में जितने भी धर्म व जाति आधारित निजी कानून हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाओं के साथ लैंगिक भेद बरतते हैं। बावजूद ये कानून विलक्षण संस्कृति और धार्मिक परंपरा के पोशक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें वैधानिकता हासिल है। इनमें छेड़छाड़ नहीं करने का आधार संविधान का अनुच्छेद–25 बना है। इसमें सभी नागरिकों को अपने धर्म के पालन की छूट दी गई है। दरअसल संविधान निर्माताओं ने महसूस किया था कि विवाह और भरण–पोषण से जुड़े मामलों का संबंध किसी पूजा–पद्धति से न होकर इंसानियत से है। लिहाजा यदि कोई निसंतान व्यक्ति बच्चे को गोद लेकर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता है अथवा इससे उसे सुरक्षा बोध का अहसास होता है तो यह किसी धर्म की अवमानना कैसे

हो सकती है। यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने के बाद उसे दरबदर भटकने की बजाय गुजारे भत्ते की व्यवस्था की जाती है तो इसमें उसका धर्म आड़े कहां आता है ? स्त्री–पुरुष के दांपत्य संबंधों में यदि समानता और स्थायित्व तय किया जाता है तो इससे किसी भी सभ्य समाज की गरिमा ही बढ़ेगी, न कि उसे लज्जित होना पड़ेगा ? लेकिन इस लैंगिक भेद को वर्तमान स्थिति से समझने की जरूरत है। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति की चार बेटियां है तो शादी से पहले चारों के समान अधिकार होते हैं। वहीं यदि एक बेटी हिंदु, मुस्लिम, तीसरी पारसी और चौथी ईसाई से विवाह करती है तो चारों के अधिकार भिन्न–भिन्न हो जाएंगे। तय है, यह कानूनी विषमता है और संविधान में दिए गए धर्म निरपेक्षता व समानता के सिद्धांत की अवज्ञा हैं।

ईसाई समाज में युवक–युवती ने यदि चर्च में शादी की है, तो उनको चर्च में आपसी सहमति से संबंध–विच्छेद का अधिकार है। किंतु यही सुविधा 'हिंदु विवाह अधिनियम'में नहीं है। यदि हिंदु युगल मंदिर में स्वयंवर रचाते हैं और कालांतर में उनमें तालमेल नहीं बैठता है तो वे चर्च की तरह मंदिर में जाकर आपसी सहमति से तलाक नहीं ले सकते ? उन्हें परिवार न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही तलाक मिलता है। जबकि यदि हम परंपरा को कायम रखना चाहते हैं तो मंदिरों को तलाक का अधिकार भी देना चाहिए ? हिंदुओं में खाप पंचायतें एक गौत्र में शादी करने की प्रबल विरोधी हैं। कई जनजातियां अपनी लोक मान्यताओं के अनुसार गांव और जाति से बाहर विवाह को वर्जित मानती हैं।

हालांकि जैसे–जैसे धर्म समुदाय शिक्षित होते जा रहे हैं, वैसे–वैसे निजी कानून और मान्यताएं निष्प्रभावी होती जा रही हैं। पढ़े–लिखे मुस्लिम अब शरिया कानून के अनुसार न तो चार–चार शादियां करते हैं और न ही तीन बार तलाक बोलकर पति–पत्नि में संबंध विच्छेद हो रहे हैं। हिंदू समाज का जो पिछड़ा तबका शिक्षित होकर मुख्यधारा में शामिल हो गया है, उसने भी लोक में व्याप्त मान्यताओं से छुटकारा पा लिया है। कुछ मामलों में उच्च और उच्चतम न्यायालओं ने भी ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं, जिनके चलते हरेक धर्मावलंबी के लिए व्यक्तिगत रूप से संविधान–सम्मत धर्मनिरपेक्ष कानूनी व्यवस्था के अनुरूप कदमताल मिलाने के अवसर खुलते जा रहे हैं। बहरहाल समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करते वक्त व्यापक राय–मशविरे की जरूरत तो है ही, यत्र–तत्र–सर्वत्र फैली लोक–परंपराओं और मान्यताओं में समानताएं तलाशते हुए, उन्हें भी विधि–सम्मत एकरूपता में ढालने की जरूरत है। ऐसी तरलता बरती जाती है तो शायद निजी कानून और मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में अदालतों को जिन कानूनी विसंगतियों और जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, वे दूर हो जाएं ?

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

धार्मिक तीर्थ स्थानों के कायाकल्प से मजबूत हो रहा है देश का अर्थतंत्र

विभाकर झा

भारत सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। देश में ऐसे अनगिनत मंदिर और तीर्थस्थल हैं, जिनसे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। इसलिए भारत में आस्था और तीर्थस्थानों का अपना एक गणितीय अर्थशास्त्र भी होता है। मन्दिरों और तीर्थस्थानों का अर्थविज्ञान देश की अर्थव्यवस्था का स्तम्भ है। बाबा काशी विश्वनाथ हो या फिर चार धाम की यात्रा, वैसे तो ये यात्राएं सीधे तौर पर धर्म और आस्था से जुड़ी नजर आती हैं। लेकिन इसके पीछे छिपा अर्थविज्ञान एक अलग ही तस्वीर दिखाता है, जो बताता है कि मंदिरों का अर्थशास्त्र भी देश की जीडीपी में अपना खास स्थान रखता है। मंदिर और दूसरे तीर्थस्थलों के बारे में आम धारणा यही है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसकी बड़ी तस्वीर ये बताती है कि भारत की जीडीपी में धार्मिक यात्राओं का योगदान 2. 32 फीसदी है और मंदिरों की इकोनॉमी करीब 3.02 लाख करोड़ की है, जिसमें फूलों की बिक्री से लेकर पूजा–पाठ से जुड़े अन्य सामान भी शामिल हैं।

एक आकलन के अनुसार 55 प्रतिशत हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं और भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक तीर्थस्थलों पर ही जाते हैं। जहां लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं। मंदिर का यही अर्थविज्ञान देश की विकास यात्रा को भी रफ्तार देता है। भारत जैसे देश में जहां आस्था का स्थान सबसे ऊपर है, वहां धर्म का अर्थशास्त्र इकोनॉमी को गति देने में काफी अहम है। NSSO का डाटा बताता है कि भारतीय बिजनेस ट्रिप से ज्यादा धार्मिक यात्राएं करते हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोरोना संकट और पलायन की समस्या से जूझ रहे उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को चार धाम की यात्रा से ही मजबूती मिली है। वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिला है। बंद पड़े होटल, रेस्त्रा, कैफे में भी पर्यटकों की आवक से रौनक रही। इस बार केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा में सिर्फ घोड़ा खच्चरों, हेलीकाप्टर टिकट के यात्रा भाड़े से ही लगभग 211 करोड़ का कारोबार हुआ है। जिसमें अकेले केदारनाथ में लगभग 190 करोड़ का कारोबार हुआ है। वहीं यमुनोत्री में भी घोड़े खच्चर कारोबारियों ने लगभग 21 करोड़ का कारोबार किया है। चारधाम यात्रा से जुड़े टैक्सी व्यवसाइयों ने भी पिछले सालों की औसत आय से तीन गुना अधिक का कारोबार किया है।

भारतीयों की धार्मिक प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने और धार्मिक स्थलों के सर्किट निर्माण पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए कई तीर्थ स्थलों के विकास से जुड़े प्रोजेक्टों पर लगातार काम चल रहा है। अयोध्या का श्रीराम मन्दिर, बाबा काशी विश्वनाथ, महाकाल कॉरिडोर, चार धाम यात्रा और बुद्धा सर्किट प्रमुख हैं। इन सर्किटों के विकास के साथ ही वहां पहुंचने के लिए रेल, सड़क और हवाई यात्राओं को सुगम बनाया जा रहा है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है जहां भारी संख्या में विदेशी तीर्थयात्री पहुंचते है। विदेशी तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए यहां की सड़कों को एंटीक स्ट्रीट लाइटिंग, लैंडस्केपिंग व फ्लोरीकल्चर से निखारा जा रहा है।

काशी कॉरिडोर और उसके कायाकल्प को कल तक जो लोग धार्मिक तुष्टिकरण के नजरिये से देख रहे थे और उसकी आलोचना कर रहे थे आज वे लोग भी महादेव के भक्तों द्वारा बनाए गए चढ़ावे के नये रिकार्ड से आश्चर्यचकित हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार 100 करोड़ मूल्य से भी ज्यादा चढ़ावा एक साल में महादेव के भक्तों ने यहां अर्पण किया है। मन्दिर को होने वाली आय से खुश मन्दिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक सुनील वर्मा कहते हैं कि आने वाले दिनों में मन्दिर से इतनी आय होगी कि चार पांच साल में ही कॉरिडोर निर्माण की लागत निकल जाएगी। यही है हमारे सनातन धर्म की शक्ति।

केदारधाम और बद्रीधाम का भी कायाकल्प किया जा चुका है। इसी का परिणाम है कि दुर्गम और बर्फीले मार्ग के बाबजूद अब वहां धार्मिक तीर्थयात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। धार्मिक स्थलों के कायाकल्प और मार्गों के सुगम होने से जहां लोगों में अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है वही स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी नए–नए अवसर खुल रहे हैं। यही नहीं दशकों आतंकवाद का दंश झेल चुके जम्मू कश्मीर में भी सरकार करीब 50 हजार मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा रही है। साथ ही धार्मिक मार्गों को सुरक्षित और सुगम भी बना रही है। जिससे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की घाटियों और वादियों को देखने की चाहत रखने वाले लोगों के साथ ही धार्मिक पर्यटन की चाहत रखने वाले लोग भी यहां आएं।

मन्दिरों के बाद देश में मनाए जाने वाले त्योहारों का भी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। दिवाली के मौके पर जहां 42 टन सोने की खरीद से कुल कारोबार 250 लाख करोड़ का हुआ तो वहीं आस्था के महापर्व छठ में भी करोड़ों का कारोबार हुआ। जाहिर है इन त्योहारों से स्थानीय स्तर पर रोजगारों की समस्या से जूझ रही जनता को न केवल रोजगार मिला बल्कि कोरोना और मंदी से हिचकोले खाती देश की अर्थव्यवस्था को हिन्दू पर्व–त्योहार, धार्मिक यात्राओं और मन्दिरों ने एक नई रफ्तार दी है।

(लेखक पत्रकार है)

ISSN No. 2581-3528

भविष्य के भारत में शिक्षक की भूमिका

डॉ. उर्विजा शर्मा

शिक्षक अंतिम नहीं, अनंतिम होता है। ज्ञान का अविरल प्रवाह भारत की गुरु–शिष्य परंपरा से आज नई राष्ट्रीय–शिक्षा नीति के रूप में हमारे समक्ष है। वस्तुतः दिशाहीनता के घटाटोप को विकीर्ण कर प्रकाश का सूर्योदय ज्ञान से ही संभव है। भविष्य के भारत में शिक्षक प्रकाशदीप बनकर भारत की उर्जावान युवाशक्ति का मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि भारत का सर्वांगीण विकास इत्यलम नहीं है। अतः भारत की महान ज्ञान परम्परा का संबल लेकर हम भविष्य के भारत का मार्ग देख पा रहे हैं। विद्या अखण्ड होती है, अविभाज्य होती है। वह यदि संस्कृति से पोषित होकर बढ़े तो सही अर्थों में अपनी लक्ष्यसिद्धि कर सकती है। यह दायित्व शिक्षकों को ही लेना होगा तभी भारत–निर्माण हो सकेगा।

शास्त्रों ने विद्यार्थी के लक्षण निम्न शब्दों में व्याख्यायित किये –

काकचेष्ठा बकोध्यानं, श्वाननिंद्रा तथैव च।

अल्पहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी चतुर्थलक्षणम।।

अर्थात् काक के समान प्रयास, बक के समान ध्यान, श्वान के समान सचेत निंद्रा, अल्पहार ग्रहण करने वाला, गृह के मोह को त्यागने वाला ही सही अर्थों में विद्यार्थी होता है। यदि देखा जाये तो शिक्षक भी एक विद्यार्थी ही होता है। एक शिक्षक में जब तक विद्यार्थी के समान जिज्ञासा का भाव होगा, सीखने की इच्छाशक्ति होगी तभी वह अपने विषय के साथ–साथ समसामयिक विषयों का व्यापक विश्लेषण कर सकेगा। वर्तमान संदर्भों की तुलना यदि हम प्राचीन गुरु–शिष्य परंपरा से करते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि 'गुरु वह होता है जो निस्वार्थ भाव से विद्यादान करें, साथ ही बदले में पारितोषिक' की कामना न करें। जबकि शिक्षक विद्या को भी व्यवसाय बना लेता है। अभिप्राय यह कि सही अर्थों में शिक्षक को केवल शिक्षा देने तथा उस शिक्षा से युवापीढ़ी को राष्ट्रनिर्माण हेतु सजग करने की आवश्यकता है। यदि शिक्षक राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें तो सही रूप में अपनी भूमिका का निवर्हन कर सकते हैं। चाणक्य इसका सबसे सही प्रमाण है, जिन्होंने चन्द्रगुप्त की प्रतिभा को पहचानकर विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध न केवल भारतभूमि की रक्षा की वरन एक सुदृढ़ राष्ट्र की स्थापना के स्वप्न को साकार भी कराया। वीर शिवाजी की प्रथम गुरु उनकी मां जीजाबाई थी। जिन्होंने अपने पुत्र को वह संस्कार दिये जिसने कठिन परिस्थिति में मुगल साम्राज्य को धूल चटाते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना करके 'स्वराज' का ध्वज फहराया। रामायण काल में भी गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, बाल्मीकि आदि महर्षियों ने रामराज्य की स्थापना के लिए श्रीराम को प्रेरणा दी। महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। समस्त आर्यावर्त सदैव ही गुरु–शिष्य परम्परा से ज्ञान परम्परा को जीवित रखने के सुकार्य में संलग्न रहा। किन्तु दुर्भाग्यवश निरंतर होने वाले आक्रमणों के कारण हम अपनी उस अमूल्य सांस्कृतिक चेतना को कहीं विस्मृत कर गये। बाकी जो कुछ भी शेष रहा उसे नालन्दा एवं तक्षशिला को नष्ट–भ्रष्ट करके समाप्त करने का यत्न किया जाता रहा। क्या कारण रहा कि आज इतिहास में पुर्नलेखन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आखिर कब सही अर्थों में राष्ट्रनायकों को वह स्थान मिल सकेगा जिसके वे अधिकारी हैं। इतिहास के नाम पर छलछद्म को समाप्त करने का समय आ चुका है। यह गुरुतर दायित्व शिक्षकों को ही उठाना होगा।

आवश्यकता है मुगलकालीन एवं ब्रिटिशकालीन इतिहास के पुनरावलोकन करके सही तथ्यों को प्रस्तुत करने की, जिससे युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत को सही अर्थों में समझ सके। शिक्षकों को अब प्रत्येक विषय को 'गुरु' की तरह अपने शिष्य रूपी विद्यार्थी को समझाना होगा। परम्परा को विज्ञान व तकनीक से जोड़ना होगा। ज्योतिष, खगोलशास्त्र, भूगोल, विज्ञान के अनुसंधानों को प्राचीन ज्ञान–परम्परा से समझना होगा। राजनीति में भी विमर्श को बढ़ावा देना होगा। समसामयिक परिवेश में शिक्षक को अपनी भूमिका एक राष्ट्रनिर्माता के रूप में निभानी होगी। सशक्त राष्ट्र के साथ विश्वगुरु बनने का यही सही समय है।

(लेखिका एस.डी.पी.जी. कॉलेज गाजियाबाद में हिन्दी विभाग की प्रोफेसर है)

ISSN No. 2581-3528

कौन वास्तव में हमारे देश के संविधान की आत्मा के लिए काम कर रहा है?

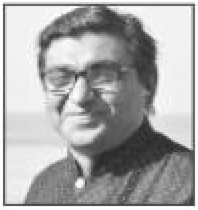

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

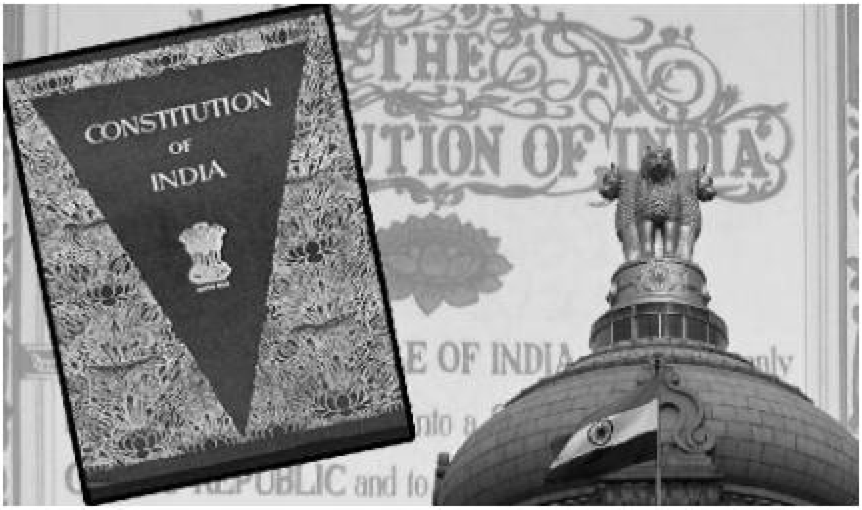

हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है– हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भारत जैसा विविध, बहुभाषी और बहु–सांस्कृतिक देश कोई दूसरा नहीं है, फिर भी यह साझी परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों के प्राचीन बंधनों से बंधा हुआ है। पारस्परिकता को प्रोत्साहित करने और भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से अद्वितीय देश में विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच एकता की एक समृद्ध मूल्य प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों और जीवन के तरीकों से लोगों के बीच बढ़ते और निरंतर पारस्परिक संपर्क के माध्यम से इस तरह के बंधन को मजबूत किया जाना चाहिए।

हालाँकि, 'ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस', जो सच्चे संवैधानिक समर्थक होने का दावा करती हैं, वास्तव में हमारी महान पवित्र पुस्तक के सबसे प्रबल विरोधी हैं। वे संविधान के प्रति अपने प्रकट प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए विमर्श को बड़े पैमाने पर सेट करते हैं, लेकिन व्यवहार में वे विरोध करते हैं और हमारे संविधान की आत्मा और दिल के खिलाफ काम करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि एकता और विविधता टूट जाए, जिसके लिए उन्होंने एक विमर्श सेट किया है और 'मेकिंग इंडिया फोर्सेस' के खिलाफ काम कर रहे हैं। नफरत इतनी प्रबल है कि वे नक्सलवाद, आतंकवाद, असामाजिक तत्वों, जाति विभाजन, धर्म परिवर्तन और भ्रष्ट नेताओं का समर्थन करते हैं। उनकी भारत विरोधी कार्रवाइयाँ और विचारधाराएं या तो विदेश से पोषित हैं या सत्ता की इच्छा से प्रेरित हैं।

विकृत इतिहास, गलत शिक्षा प्रणाली, और भारत के मूल विचार के खिलाफ नियमित आधार पर घृणित आख्यानों का अंतिम लक्ष्य एकता को तोड़ना, भारत की प्राचीन संस्कृति जिस पर हमारे संविधान की आत्मा आधारित है, जो एकता, अखंडता, समभाव और विश्वगुरु बनाने में विश्वास करती है जो संतुलित और तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ पूरी दुनिया की देखभाल करना सिखाती है।

हालांकि हमारे संविधान में विभिन्न विदेशी दस्तावेजों से कई प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय है। यह हमारे संविधान की सुंदरता, समावेशिता और व्यापकता को दर्शाता है। प्रस्तावना उस आशय को स्पष्ट करती है, जो महान भारतीय प्राचीन संस्कृति के अनुरूप है।

संविधान के अनुसार सामाजिक समरसता, एकता और अखंडता में विश्वास न रखने वाली भारत को तोड़ने वाली ताकतें डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और उनके संविधान की ड्राफ्टिंग टीम के सपनों को साकार करने के लिए जमीन पर काम कर रहे संगठनों को नष्ट करने के लिए दिन–रात काम करती हैं। ऐसा ही एक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), इन तोड़ने वाली ताकतों द्वारा विशेष रूप से तिरस्कृत है। आरएसएस की जहरीली आलोचना की जा रही है, उसके खिलाफ लगातार जहरीली बातें गढ़ी जा रही हैं, लेकिन वे सभी के साथ समान व्यवहार करने के लिए सामाजिक समानता के मंत्र का पालन करते हुए बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों को एकजुट करने के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं, ताकि हर कोई देशहित मे कार्य करने के लिए हाथ मिलाए जिससे एक महान राष्ट्र का निर्माण करना जहाँ हर कोई सामाजिक आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्तिगत और

सामूहिक रूप से स्वयंसेवकों के सामाजिक जागरण और चरित्र विकास के माध्यम से प्रणालीगत परिवर्तन को प्रभावित करना चाहता है। संघ अपने स्वयंसेवकों से कुछ गुणों की अपेक्षा करता है। वे समाज में संघ के मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करेंगे; वे अखिल भारतीय दृष्टिकोण को कायम रखेंगे कि रामसेतु से लेकर हिमालय तक यह देश एक है और मेरा अपना है; उनका दृढ़ विश्वास होगा कि समाज के सभी सदस्य समान हैं; राष्ट्र को अपने से ऊपर रखने के लिए वे नियमित रूप से शाखा में भाग लेंगे और सहजता से आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।

इस तथ्य के बावजूद कि आरएसएस के सभी संगठन प्रत्येक वर्ग और विषय की बेहतरी के लिए काम करते हैं, जैसे कि जनजाती, अन्य सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय, किसान, मजदूर, युवा, सामाजिक एकता, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर भारत, सामाजिक आर्थिक विकास आदि। इस खंड में दो संगठनों, सेवा भारती और वनवासी कल्याण आश्रम के बारे में जानकारी है, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि अच्छे इरादों के साथ संविधान का पालन कैसे किया जाता है।

सेवा भारती के स्वयंसेवक वर्तमान में देश के दूरस्थ क्षेत्रों में 100,000 से अधिक सेवा परियोजनाओं में शामिल हैं। बाढ़, दुर्घटनाओं, भूकंप और सुनामी जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं सहित कई प्राकृतिक आपदाओं के लिए स्वयंसेवक सबसे पहले उत्तरदाता रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, सेवा भारती में 17,500 शिक्षा परियोजनाएँ, 12,000 स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाएँ, 26,000 सामाजिक कल्याण परियोजनाएँ और 9238 आत्मनिर्भरता परियोजनाएँ हैं। चिकित्सा सहायता, पुस्तकालय, छात्रावास, बुनियादी शिक्षा, वयस्क शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण, और सड़क पर रहने वाले बच्चों और कोढ़ियों का उत्थान उन परियोजनाओं में से हैं जो समाज के आर्थिक रूप से वंचित और सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों की सेवा करते हैं। सेवा भारती की परियोजनाओं का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को उनके जीवन के सभी पहलुओं में आत्मनिर्भर बनाना है।

वनवासी कल्याण आश्रम : भारत विविध प्राकृतिक पर्यावरण और अनूठी सांस्कृतिक विरासत वाली भूमि है। यह सैकड़ों जनजातियों का घर भी है, जिन्हें 'वनवासी' भी कहा जाता है। हमारे देश के सभी प्राचीन शास्त्रों और साहित्य में वनवासियों का उल्लेख मिलता है। रामायण में शबरी, बाली, सुग्रीव आदि जैसे कई संदर्भ हैं, जबकि महाभारत में एकलव्य, बार्बरीक, घटोत्कच आदि जैसे संदर्भ हैं। रांची क्षेत्र (झारखंड राज्य) में बिरसा मुंडा, महाराष्ट्र में कान्होजी भांगरे, केरल में तलक्कल चंदू, उड़ीसा में विशोई, मेघालय में तिरोत सिंग, बिहार में संथाल नेता (सिद्दो, कानू और तिलका मांझी), मणिपुर की रानी गैदिन्ल्यू और शाहिद जादोनांग राजस्थान के पुंजा भील स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने वालों में थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले और भी कई जनजातियां गुमनाम नायक हैं।

जनजातियां हमारे देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत हैं, और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को छोड़कर लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जाती हैं। वे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बने हुए हैं। बदकिस्मती से कलंक और आपराधिकता देश के कुछ शहरवासियों द्वारा समाज के इस वर्ग के साथ पीढ़ियों से जुड़ी रही है। यह जरूरी है कि समाज वनवासियों और उनकी समृद्ध संस्कृति का सम्मान करे।

वनवासी कल्याण आश्रम वर्तमान में 455 जनजाति जिलों में से 361 में कार्यरत है। कुल 19398 सक्रिय परियोजनाएं हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए कई शैक्षिक केंद्र और छात्रावास स्थापित किए गए हैं, साथ ही कृषि विकास और कौशल विकास केंद्र, स्वयं सहायता समूह, चिकित्सा सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्र विकास, और हमारे जनजाती भाइयों और बहनों की सहायता के लिए कई अन्य पहल की गई हैं।

सरकार में संघ के स्वयंसेवक : सारांश वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने वाले मुख्य न्यायाधीश श्रीमान सीकरी सहित केशवानंद भारती मामले में तेरह न्यायाधीशों में से सात ने कहा कि संसद की शक्ति में अंतर्निहित सीमाएं हैं। संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान की 'मूल संरचना' या ढांचे को 'नुकसान', 'निष्क्रिय', 'नष्ट', 'निरस्त', 'बदलाव' करने के लिए नहीं कर सकती। इस तथ्य के बावजूद, कई राजनीतिक दल मोदी सरकार और आरएसएस को मौलिक संरचना को बदलने की कोशिश के रूप में चित्रित करने का प्रयास करते हैं।

वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ मुख्यमंत्री और कई अन्य मंत्री संघ की पृष्ठभूमि से हैं, और उनका काम दर्शाता है कि संविधान की आत्मा और दिल का सम्मान कैसे किया जाता है। कई योजनाएं सभी जातियों और धर्मों के गरीब और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों को लाभ प्रदान करती हैं, जिनमें मुफ्त आवास, सिलेंडर, खाद्यान्न, शौचालय, बैंक खाते, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सहायता और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के साथ–साथ गाँव, गरीब और जनजाती समुदायों के वर्तमान नायकों को प्रसिद्धी और सम्मान जो समाज और देश की भलाई के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर, 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा की। उसके बाद, वित्त मंत्री ने अपने 2016–17 के बजट भाषण में इस पहल की घोषणा की। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच बेहतर समझ और जुड़ाव पैदा होगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ विभिन्न भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच बातचीत को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के अनुसार, प्रत्येक वर्ष, भारत में प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क के लिए भारत के दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। आशा है कि इस आदान–प्रदान के माध्यम से विभिन्न राज्यों की भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से अधिक समझ और जुड़ाव पैदा होगा, जिससे संविधान के अनुसार भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी।

जैसा कि भारत विरोधी ताकतों द्वारा निर्धारित आख्यानों के बजाय हमें जमीन पर वास्तविक काम से पता चलता है कि आरएसएस और उसके संगठन वास्तव में संविधान की आत्मा और ह्रदय के अनुसार काम कर रहे हैं।

(लेखक ब्लॉगर एवं शिक्षाविद हैं)

ISSN No. 2581-3528

इमामों को वेतन तो मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं?

डॉ. प्रीता पंवार

स्वतंत्रता कहां सहज मिली भारत को! धर्म के नाम पर विभाजन की भयावह त्रासदियां झेलीं भारत भूमि ने! एक ओर भारत से टूट कर विशुद्ध इस्लामिक पाकिस्तान बना तो दूसरी ओर भारत एक प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन कर उभरा। इसी धर्मनिरपेक्षता का भाव इस्लामीकरण की ओर ले जाने वाला पहला कदम बना। वोटों की राजनीति सर्वोपरि हो गई और इसके साथ ही मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियां भी परवान चढ़ती गईं और स्वतंत्र भारत में वो ही पुरानी विभाजनकारी, भयावह अवधारणाएं पनपनें लगीं जो पाकिस्तान के जन्म के मूल में थीं। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और साम्यवादी ताकतें भारत की जड़ों को पुनः खोखला करने लगीं। धर्मनिरपेक्षता कहां सच्ची धर्मनिरपेक्षता रही! धर्मनिरपेक्षता उपहास बन कर रह गई और और फिर शुरू हो गई – अल्पसंख्यक –बहुसंख्यक विवादों की अंतहीन श्रृंखलाएं! बहुसंख्यकों पर हावी होते अल्पसंख्यक! और इसके साथ ही समाज के बदलते स्वरूप! लुप्त होती राष्ट्रीयता! दम तोड़ती सनातनी सभ्यता! धर्मनिरपेक्षता कहां धर्मांधता को रोक पाई! कश्मीर, केरल और बंगाल इसके ज्वलंत उदहारण हैं।

इसी संदर्भ में एक अहम मुद्दा मौलवियों के वेतन को लेकर है। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने बहुत ही सटीक टिपण्णी दी है कि इमाम को वेतन तो पुजारी को क्यों नहीं? यदि मस्जिद के इमामों को सरकारी खजाने से पैसा दिया जा रहा है और यह पैसा देना सही है तो फिर यह वेतन मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे में ग्रंथी को क्यों नहीं दिया जा सकता? यह सवाल लंबे समय से चौक–चौराहों की चर्चाओं में शामिल होता रहा था लेकिन केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर की टिप्पणी के बाद देश भर में इस मुद्दे पर बहस प्रारंभ हो गई है। संविधान जब कहता है कि देश में सभी नागरिक और धर्म समान हैं, फिर किसी एक मजहब को चुनी हुई सरकार द्वारा विशेष सुविधा क्यों? मुख्य सूचना आयुक्त की टिप्पणी का मामला दिल्ली सरकार द्वारा इमामों के वेतन से जुड़ा है।

सुभाष अग्रवाल एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं। वे आरटीआई अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली की मस्जिदों में इमामों को वेतन देने के फैसले से संबंधित जानकारी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आवेदन लगाया था। अग्रवाल ने दिल्ली के अंदर उन मस्जिदों की संख्या जानने की भी कोशिश की, जहां इमामों को सरकारी खजाने से नियमित वेतन दिया जा रहा है। अग्रवाल ने यह भी जानना चाहा कि इमामों को दिए जाने वाली कुल राशि कितनी है, वार्षिक खर्च में उन पर कितना भुगतान किया जा रहा है। अग्रवाल ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह भी जानना चाहा कि क्या हिंदू मंदिरों के पुजारियों को भी वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो दिल्ली सरकार में इमामों को उपलब्ध है। यह सवाल उन्होंने दिल्ली के उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यालयों से पूछा भी लेकिन उन्हें अपनी आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं मिला। उनके सवाल को मुख्य सचिव के कार्यालय ने राजस्व विभाग और दिल्ली वक्फ बोर्ड को भेज दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अग्रवाल को अपने जवाब में कहा कि कोई भी प्रश्न उनसे संबंधित नहीं है। इससे तय हो गया कि जवाब वहां से मिलना नहीं है। इसके बाद मामला सूचना आयुक्त के पास पहुंचा। सूचना आयुक्त ने इन दोनों विभागों के जन सूचना अधिकारियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए पेश होने को कहा। सीआईसी ने दोनों विभाग के अधिकारियों से मामले से जुड़ी सारी फाइलें सुनवाई के लिए लाने को भी कहा। उसके बाद जो कुछ हुआ, उसकी उम्मीद तो प्रश्न

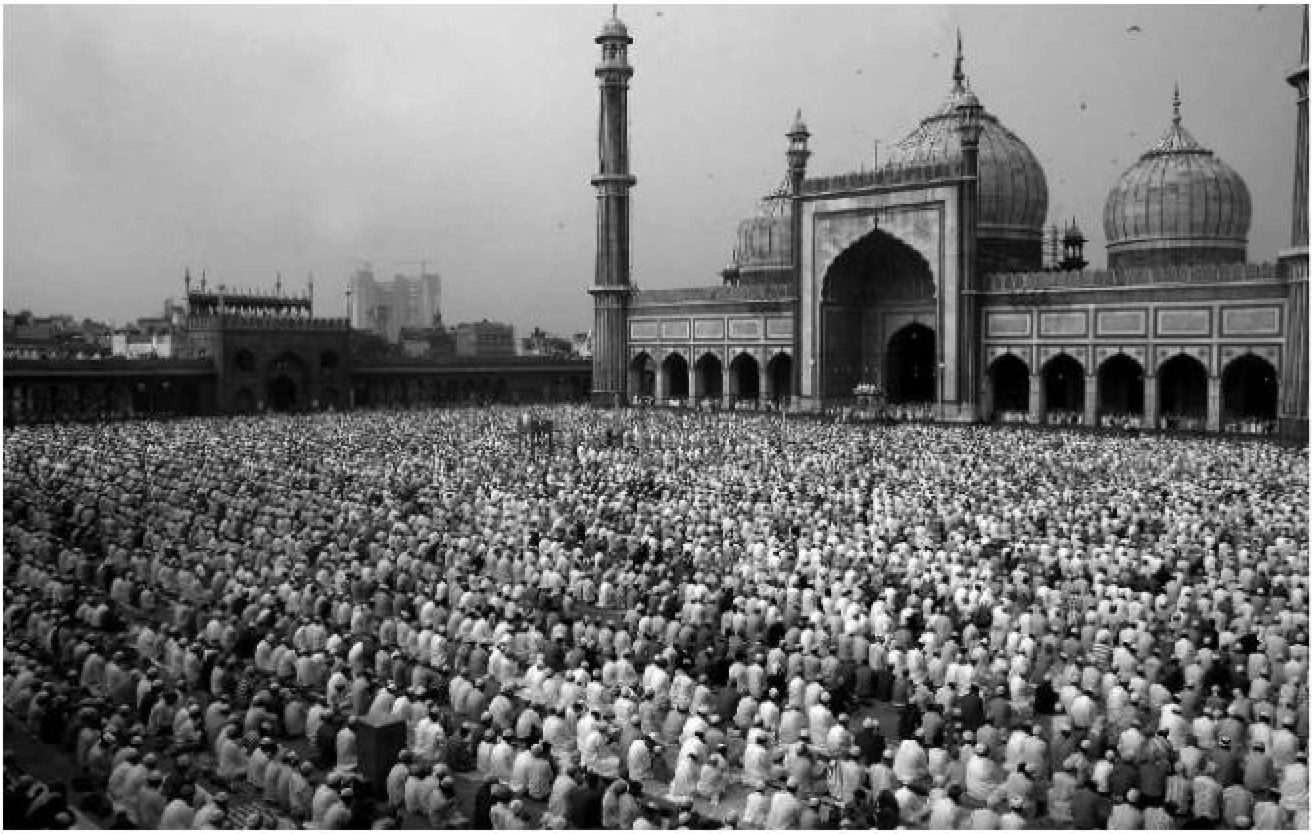

पूछने वाले सुभाष अग्रवाल को भी नहीं होगी। उनके द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सूचना आयुक्त ने कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला संविधान के अनुरूप नहीं है। करदाताओं के पैसे को किसी धर्म विशेष पर खर्च करना गलत है। ये बात संविधान के आर्टिकल 27 में कही गई है।

यहां केंद्रीय सूचना आयुक्त यह कहना चाह रहे थे कि 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने इमामों को तनख्वाह देने को सही ठहराया था वो निर्णय संविधान के अनुरूप नहीं है। सूचना आयुक्त का यह भी कहना था कि इससे अलग–अलग धर्म और वर्ग के लोगों के बीच में एक गलत संदेश गया है। सूचना आयुक्त माहुरकर का कहना था कि इससे न केवल देश में एक गलत संदेश गया, बल्कि समाज में द्वेष की भावना भी पनपी है। अपने जवाब में सूचना आयुक्त ने कहा कि 1947 से पहले भी मुसलमानों को विशेष प्रावधान के अन्तर्गत रियायतें हासिल हुई थीं। किन्तु वो अंग्रेजों का राज था। उनका एक मात्र ध्येय था फूट डालो और राज करो। अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब रहे तथा हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। 4 करोड़ मुसलमान 29 करोड़ हिन्दुओं पर भारी पड़ गए क्योंकि मुसलमानों को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। किन्तु विडंबना यह रही कि स्वतंत्रता के बाद भी सरकार ने मुसलमानों को संरक्षण देना जारी रखा, जिसने देश को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार के विशेषाधिकारों ने भारत के बंटवारे में तुष्टीकरण की भूमिका अदा की। अपने आदेश में सूचना आयुक्त का कहना था कि दिल्ली सरकार हर साल वक्फ बोर्ड को 62 करोड़ रुपये का अनुदान देती है, जबकि वक्फ की अपनी आमदनी मात्र 30 लाख मासिक है। इस तरह दिल्ली में वक्फ बोर्ड इमामों को पारिश्रमिक देने के लिए करदाताओं के धन का उपयोग कर रहा है।

दिल्ली में कुछ समय पहले यह बात सामने आई थी कि दिल्ली सरकार द्वारा मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम को हर माह 16 हजार और 18 हजार रूपया वेतन के रूप में दिया जाता है। यह भारत के अलग अलग धर्मों में विभाजन पैदा करता है। सूचना आयुक्त के अनुसार जितनी बातें उनके संज्ञान में लाई गई, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए ये मसले बेहद अहम हैं। आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी अनुशंषा की है कि संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 को लागू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा सुनाया गया यह निर्णय ऐतिहासिक है। सूचना आयुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इमामों को तनख्वाह देने के फैसले को सही ठहराया था वो संविधान के अनुरूप नहीं है। निःसंदेह धर्म निरपेक्षता का अर्थ किसी विशेष धर्म का संरक्षण कदापि नही और उस धर्म का तो कतई नहीं जो भारत के विभाजन का तथा उससे जुड़ी अंतहीन विभीषिकाओं का निमित्त रहा हो।

(लेखिका स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद की भूतपूर्व प्राचार्या, हैं)

ISSN No. 2581-3528

रोड शो से सँवरता उत्तर प्रदेश का निवेश परिवेश

डॉ. मनमोहन सिंह

वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद किए गए कार्यों एवं कार्यशैली से योगी आदित्यनाथ ने आलोचकों, विरोधियों एवं एजेन्डाधारियों की आशंकाओं को बिल्कुल निर्मूल सिद्ध किया है। भगवाधारी संत एवं राम–जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े प्रतिष्ठित गोरखनाथ मठ के महंत होने के कारण अनेकों भारत एवं सनातन विरोधियों ने उन्हें अनुभवहीन बताकर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ने की भविष्यवाणी की थी। उन एजेन्डाधारियों के लिए आज यह पचा पाना मुश्किल है कि कैसे एक भगवाधारी योगी प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा, समरसता एवं आर्थिक स्थिति के उन्नयन में नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ने जहां रोड शो को केवल बाहुबल एवं धनबल के प्रदर्शन तथा चुनावी मौसम में मतदाताओं को लुभाने के माध्यम के रूप में ही देखा था, वहीं योगी सरकार ने उसे देश–विदेश में प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाने एवं निवेशकों को आकर्षित करने के प्रभावी यंत्र के रूप में स्थापित किया है। टीम योगी निवेशकों, उद्योगपतियों एवं फिल्म निर्माताओं के सामने बदले हुए उत्तर–प्रदेश का चित्र प्रस्तुत कर रही है। ऐसा चित्र जिसमें निवेश के रंग भरे जाने की अपार संभावनाएं हैं। व्यापार के देशी एवं विदेशी केंद्रों तक मुख्यमंत्री अथवा उनकी टीम स्वयं पहुँच रहे हैं और निवेश की लिहाज से नए उत्तर प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ स्थान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। टीम द्वारा नए उत्तर प्रदेश में बिजली, आधारभूत सुविधाओं, ऐक्सप्रेसवे, मेट्रो एवं एयरपोर्ट आदि के निर्माण के आधार पर निवेशकों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के वर्ष 2024–25 तक देश को 5–ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर–प्रदेश को सम्पूर्ण भारत के विकास इंजन के रूप में स्थापित करने का बीडा उठाया है। प्रधानमंत्री के लक्ष्य में सहभागी बनते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024–25 तक 1–ट्रिलियन डॉलर करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि हेतु उन्होंने आरंभ से ही ऐक्सप्रेसवे निर्माण, डाटा सेंटर स्थापना, शिक्षा/ स्वास्थ्य संस्थान एवं मेट्रो निर्माण के साथ ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनस हेतु निवेश फ्रेंडली नीतियाँ बनाने एवं एम. एस. एम. इकाइयां आरंभ करने पर जोर दिया है। निवेश आकर्षित करने के लिए निवेश मित्र जैसे एकल खिड़की (सिंगल विंडो) पोर्टल के निर्माण के साथ ही कानून–व्यवस्था तथा बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश में निवेश को नई ऊंचाइयों तक पहुचाने के उद्देश्य से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10–12 फरवरी 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है।

ISSN No. 2581-3528

देश में होने वाले अनेकों सरकारी आयोजनों की तरह यह भी मात्र एक औपचारिकता बनकर न रह जाये, इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे हैं। दुर्भाग्य से प्रदेश के मंत्रियों एवं अधिकारियों की विदेश यात्राओं को सरकारी खर्चे पर महंगी छुट्टी मनाने, अय्याशी करने तथा धनशोधन जैसे उद्देश्यों से ही जोड़कर देखा जाता रहा है। परंतु आज प्रदेश सरकार 16–देशों में मंत्रियों एवं अधिकारियों की टीम को एक स्पष्ट लक्ष्य एवं जवाबदेही के साथ भेजती है। देश तथा शहरों का चुनाव भी इस आधार पर होता है कि कहाँ व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है और कहाँ अधिकतम निवेशकों से वार्ता संभव है? बैठकें न केवल होटलों एवं बंद कमरों तक सीमित हैं अपितु रोड शो के माध्यम से देश एवं प्रदेश की विशिष्टताओं एवं उत्पादों को भी वहाँ के व्यावसायिक समुदाय के समक्ष प्रदर्शित किया जा रहा है। निवेशकों तक खुद पहुँचकर अपने प्रदेश के उत्पादों का विज्ञापन करना मुख्यमंत्री योगी की लीक से अलग सोच को रेखांकित करता है। नए उत्तर प्रदेश का नेतृत्व यह रेखांकित करने में सफल दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश न केवल सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है बल्कि भारत का सबसे बड़ा बाजार भी है जहां हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, दवाई/मेडिकल संयंत्र निर्माण, टूरिजम, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वाहन, रक्षा, एरोस्पैस, हॉर्टिकल्चर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एवं डाटा सेंटर जैसे अनगिनित क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। सोलह देशों के इक्कीस व्यापारिक शहरों में किए गए रोड शो का ही परिणाम है कि अब तक 7.12 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और सिलसिला अभी भी अनवरत जारी है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, दुबई, बेल्जियम, स्वीडन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे अनेकों देशों के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। टीम उत्तर प्रदेश के ये प्रयास समिट में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील के पत्थर सिद्ध होंगे। उम्मीद की जा सकती है कि उत्तर–प्रदेश अवश्य ही नए भारत के विकास का इंजन बनेगा। भारतीय निवेशकों को उत्तर–प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी ने स्वयं मुंबई पहुँच उद्योग एवं फिल्म जगत के दिग्गजों से मुलाकात कर उन्हें इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

मुंबई में वह टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज, आदित्य बिड़ला, पीरामल, पारले एग्रो, डिज्नी आदि समूहों के प्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे। साथ ही हिंदुजा, हिंदुस्तान युनी लीवर, हीरानन्दानी, टोरेंट पावर, वॉकहार्ड, हीरो साइकिल, एल0 एण्ड टी0 के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात संभव है। बतौर मुख्यमंत्री वह स्वयं इन निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और अवसरों की जानकारी देंगे। यह दीगर है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी के रूप में स्थापित है और वहाँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालयों से लेकर वित्तीय संस्थानों के दफ्तर भी स्थित हैं। देश की राजधानी के समीप होने एवं योजनाबद्ध तरीके से बसाये गए उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र में मुंबई का विकल्प बनने की अपार संभावनाएं हैं। इसी दिशा में कार्य करते हुए यमुना प्राधिकरण ने 250 एकड़ क्षेत्र में फिन–टेक (टेक्नॉलजी आधारित वित्तीय उद्योग) सिटी बसाने की योजना बनाई है। इसमें वित्तीय संस्थान, बैंक, ऋण प्रदाता कंपनियां, वित्तीय सलाहकार, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, वित्त नियामक संस्थाएं आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। निवेश से जुड़े सरकारी कार्यालय भी यहाँ ही होंगे। निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट के कारण नोएडा क्षेत्र में देशी–विदेशी निवेशकों की पहले से ही निगाहें लगी हुई हैं।

देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य का संधान करने में मुख्यमंत्री योगी कोई कोर–कसर नहीं छोड़ना चाहते। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश की पूरी क्षमता एवं संसाधनों का लाभ प्रदेश वासियों को मिले। देश के बड़े व्यापारिक संस्थानों एवं समूहों से प्रदेश में निवेश का आह्वान वह मुंबई के अतिरिक्त देश के अन्य व्यापारिक शहरों में भी करेंगे। यह दीगर है कि वह यू0 पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लखनऊ में शामिल होने के लिए स्वयं विभिन्न प्रदेशों में जाकर व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं। भावना के अनुरूप वह निवेशकों से उत्तर प्रदेश के बदलाव की यात्रा का सहयोगी एवं हितधारक बनने का आह्वान करते हैं। इस माध्यम से वह उत्तर प्रदेश के उत्पादों एवं यहाँ की पहचान को दुनिया के सामने रख रहे हैं। भारत आज उस जगह खड़ा है जब वह हाल ही में दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और वह भी सदियों भारत को गुलामी का दंश देने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। सौभाग्य से इसी साल भारत जी–20 के देशों का नेतृत्व भी कर रहा है।

मुख्यमंत्री योगी भारतवर्ष के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उन्नयन के यज्ञ में आहुति देने में उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं देखना चाहते। वास्तव में लगता है कि वह उत्तर प्रदेश को देश की विकास रूपी रेलगाड़ी का इंजन बनता देखने के लिए कटिबद्ध हैं। दूसरे प्रांतों में जाकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आज का उत्तर प्रदेश नया उत्तर प्रदेश है और अभी तक के बदलाव सिर्फ एक शुरुआत हैं तथा उन्हें उत्तर प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थान के नए सोपान गढ़ने से कम कुछ मंजूर नहीं है। जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की बदहाल स्थितियों में लौटे प्रवासी श्रमिकों को सहायता एवं अवसर उपलब्ध कराए वह आज भी इस वर्ग में एक आत्मविश्वास पैदा करता है। इतिहास में शायद ही ऐसे उदाहरण हों जब किसी प्रदेश सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए देश–विदेश में रोड–शो किए हों। यह और भी आश्चर्यचकित करने वाला है कि यह सब एक भगवाधारी कर रहा है।

उत्तर प्रदेश की यह शुरुआत दीर्घकाल तक अन्य प्रदेशों के सत्ताधीशों को भी जनता की समृद्धि के लिए समर्पित हो कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। (लेखक के निजी विचार)

(लेखक गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में भौतिकी विज्ञान विभाग में शिक्षक हैं)

ISSN No. 2581-3528

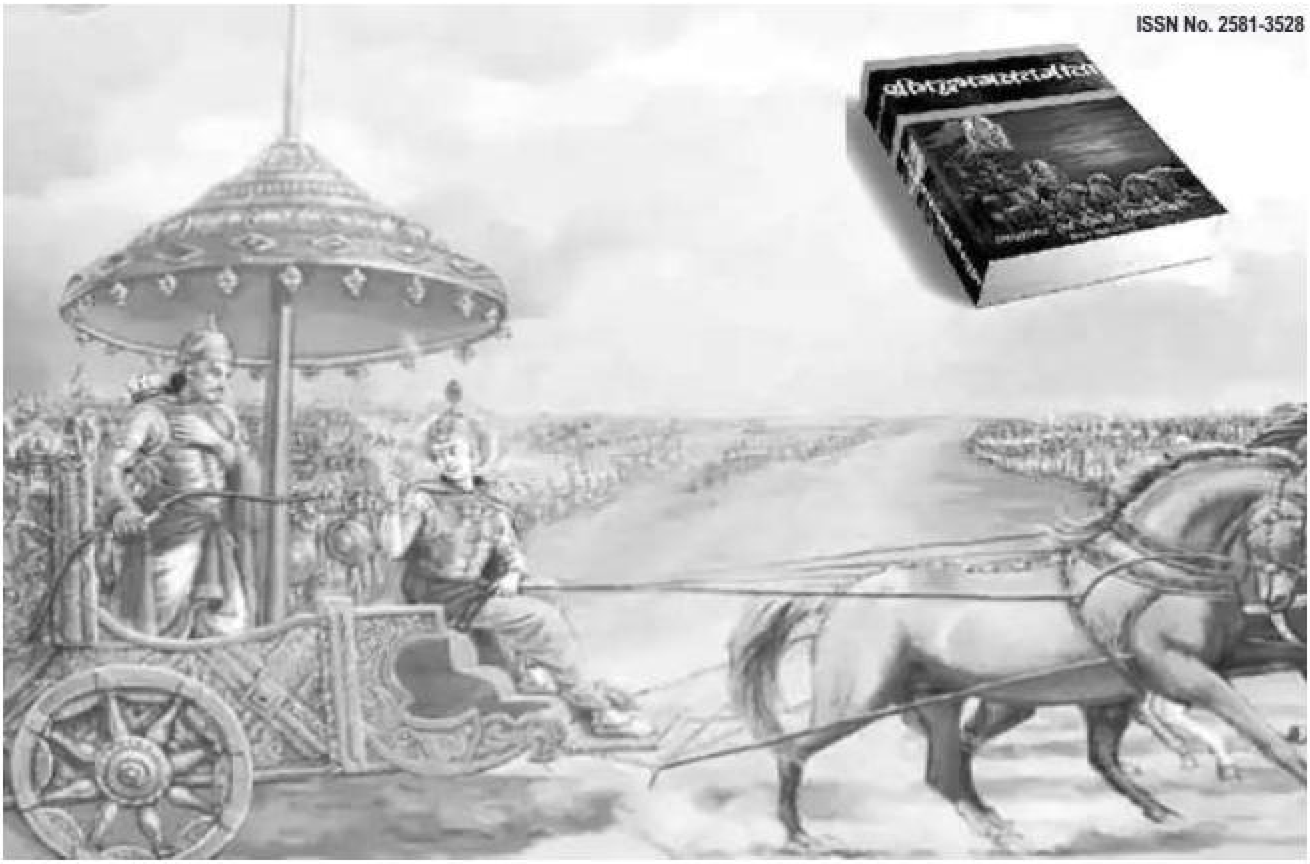

जब भी इसे पढ़ती हूँ, कुछ नया पाती हूँ!!

नीलम भागी

दुबई में मेरी जर्मन सहेली कात्या मूले अपनी किताबों का संग्रह दिखाने लगी तो वहाँ अंग्रेजी में अनुवाद गीता देखते ही मैंने उससे पूछा, ''गीता पढ़ कर तुम्हें कैसा लगा?'' उसने गीता को उठाया, उस पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया,''जब भी इसे पढ़ती हूँ, कुछ नया पाती हूँ।''

और मुझे अपनी दादी याद आने लगी, जिसका शस्त्र था संस्कृत और गीता। वह गीता को जरी गोटे के खूबसूरत कपड़े में लपेट कर रखती थीं। सुबह नहा कर जैसे ही वह गीता हाथ में लेंती, आस पास की अनपढ़ महिलाएं तुरंत हमारे आंगन में आकर उनका आसन बिछातीं, चौकी रखतीं। दादी सामवेद की ऋचा की तरह ऊँची आवाज में गीता का श्लोक पढ़तीं। जिनकी आंगन की दीवार ऊँची थी, वे आवाज सुन कर दौड़ती हुई आतीं। फिर दादी उसका अर्थ समझातीं। जब मैं संस्कृत पढ़ने लगीं। तो मैंने अम्मा से कहा,''दादी श्लोकों का गलत अर्थ बताती हैं।''सुन कर अम्मा मुस्कुराते हुए बोलीं,''मुझे पता है, अगली बार इसी श्लोक का अर्थ दूसरा होगा। तू स्कूल जाती है, मैं तो रोज सुनती हूँ। बेटी, माताजी असाधारण महिला हैं। महिलाएं इनसे दिल की बात करती हैं। जिसको ये टारगेट करती हैं उसे जो समझाना होता है, वैसा ही इनका अर्थ होता है। गीता हम लोगों के जहन में रहती है। इसलिए संस्कृत में श्लोक बोल कर ही अर्थ करतीं हैं। इनका बहू बेटियाँ भी कितना सम्मान करतीं हैं!'' दोपहर को दादी मोहल्लेदारी करने जातीं थीं। वहीं से वह श्लोक के अर्थ की तैयारी करती थीं, श्लोक कोई भी हो सकता। अगले दिन जिसे गीता के माध्यम से समझातीं थीं। दादी को सिर्फ पढ़ना आता था। उनकी इस आदत ने मेरा गीता के प्रति लगाव पैदा कर दिया। उत्कर्शिनी की बेटी के जन्म पर उस साल गीता की 151वीं जयंती थी। हमने उसका नाम गीता रख दिया।

गीता जयंती (3 दिसम्बर) का उत्सव मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकदशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 19 नवम्बर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के आस पास 300 से अधिक राष्ट्रीय स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ के 75 तीर्थों पर इस दौरान गीता पूजन, गीता यज्ञ, अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार, गीता पाठ, वैश्विक गीता पाठ, संत सम्मेलन आदि मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तीर्थयात्री कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा करके गीता महोत्सव मनाते हैं। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से 4 दिसम्बर तक होंगे। 4 दिसम्बर

ISSN No. 2581-3528

को दीपदान होगा। गीता पढ़ना, घर में रखना हमारे यहाँ परंपरा है। 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में चारों वेदों का संक्षिप्त ज्ञान है। गीता जयंती के दिन श्रीमदभागवत गीता के अलावा भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास की भी पूजा की जाती है।

पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। ऐसी भी मान्यता है कि यही ज्योतिसर तीर्थ वह पावन धरती है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता रुपी अमृतपान कराया था। यहां एक प्राचीन सरोवर और एक पवित्र अक्षय वट है जो भगवान श्रीकृष्ण के गीता उपदेश का एकमात्र साक्षी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी से मोह का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं।

हॉर्नबिल उत्सव (1 से 10 दिसम्बर नागालैंड) नागालैंड की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है तो जाहिर है त्यौहार भी खेती के आसपास ही घूमते हैं। पर हॉर्नबिल उत्सव! ये हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर है जिसके पंख सिर पर लगाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। बहादुर नायकों की प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं। तरह तरह के पकवान, लोकनृत्य और कहानियाँ इस त्योहार का हिस्सा हैं। इस उत्सव पर नागा संस्कृति देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं।

कुंभलगढ़ उत्सव (1 से 3 दिसम्बर) को कुंभलगढ़ किले में मनाया जाता है। इसमें अलग अलग संस्कृतियों से जुड़े कार्यक्रम को देखने देशी विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं।

कार्थिगाई दीपम (6 दिसम्बर) हिन्दू तमिलों, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और श्रीलंका में यह रोशनी के त्यौहार को कार्तिगई पूर्णिमा कहा जाता है। केरल में इस त्यौहार को त्रिकार्तिका के नाम से जाना जाता है जो देवी कार्तियेनी (चोटनिककारा अम्मा) भगवती के स्वागत के लिए मनाया जाता है। शेष भारत में, कार्तिक पूर्णिमा अलग तारीख में मनाया जाता है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में 'लक्षभा' के नाम से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के घरों में कार्तिक मासालु (माह) को बहुत शुभ माना जाता है। स्वामीनारायण संप्रदाय भी इस त्यौहार को बहुत उत्साह से मनाता है।

दत्तात्रेय जयंती (7 दिसम्बर) त्रिगुण स्वरुप यानि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का सम्मलित स्वरुप, इसके अलावा भगवान दत्तात्रेय जी को गुरु के रूप में पूजनीय, की जयंती मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय, महर्षि अत्रि और उनकी सहधर्मिणी अनुसूया के पुत्र थे। इनके पिता महर्षि अत्रि सप्तऋषियों में से एक हैं और माता अनुसूया को सतीत्व के रूप में जाना जाता है। राजा कार्तीवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु भगवान दत्तात्रेय के अनन्य भक्तों में से एक हैं। ऐसी मान्यता है कि दत्तात्रेय नित्य सुबह काशी में गंगाजी में स्नान करते थे। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका, दत्त भक्तों के लिए पूजनीय स्थान है। इसके अलावा मुख्य पादुका स्थान कर्नाटक के बेलगाम में स्थित है। देशभर में दत्तात्रेय को गुरु के रूप मानकर इनकी पादुका को नमन किया जाता है। भगवान दत्त के नाम पर दत्त संप्रदाय का उदय हुआ। नरसिंहवाडी दत्ता भक्तों की राजधानी के लिए जाना जाता है। कृष्णा और पंचगंगा नदियों के पवित्र संगम पर स्थित, महाराष्ट्रीयन इतिहास के प्रसंगों में इसका व्यापक महत्व है। दक्षिण भारत सहित पूरे देश में इनके अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं।

गलदान नामचोट (18 दिसम्बर) प्राकृतिक सुन्दरता के साथ, लद्दाख में नामचोट उत्सव के समय जाना सोने पर सुहागा है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें तिब्बती विद्वान को सम्मानित करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं द्वारा नाटक किए जाते हैं।

शिल्पग्राम महोत्सव (21 से 30 दिसम्बर) उदयपुर के शिल्पग्राम के उत्सव में एक जगह पर देशभर की संस्कृति की झलक देश भर से आये कलाकारों के आने से देखने को मिलती है। कला, संस्कृति, खानपान और वेषभूषा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

विद्वानों का मानना है जो जनजातियां नाचती गाती नहीं–उनकी संस्कृति मर जाती है।

नृत्य, गायन उत्सवों की शुरूआत भारत के मंदिरों में हुई थी। लेकिन अब देश विदेश से इन उत्सवों को देखने पर्यटक आते हैं।

दिसबंर में आयोजित उत्सव सनबर्न फेस्टिवल (गोवा, 28 से 30दिसम्बर) संगीत नृत्य संगीत प्रेमियों के लिए, माउंट आबू विंटर फैस्टिवल (राजस्थान, 30 और 31 दिसम्बर) लोकनृत्य, संगीत घूमर, गैर और धाप, डांडिया, शामें कव्वाली, रण उत्सव (गुजरात 1 नवम्बर से 20 फरवरी) रेगिस्तान में सांस्कृतिक कार्यक्रम गरबा लोक संस्कृति आदि।

श्री क्षेत्र उत्सव पुरी की परंपराओं को जीवित करती रेत की कला, ममल्लपुरम डांस फेस्टिवल (चेन्नई 25 दिसम्बर से 20 दिन तक चलने वाला नृत्य उत्सव) खुले आकाश के नीचे, नृत्य संगीत, शास्त्रीय और लोक नृत्य, कोचीन कार्निवाल मनोरंजन कार्यक्रम है जो हर साल दिसंबर के अंतिम दो सप्ताह तक मनाया जाता है। केरल के कोच्चि में फोर्ट कोच्चि में वास्कोडिगामा स्क्वायर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फैहरा कर उदघाटन किया जाता हैं। एक जनवरी को कार्निवाल का विशाल जुलूस है जिसका नेतृत्व हाथी करते हैं और नृत्य मुख्य आर्कषण हैं।

विष्णुपुर महोत्सव 27 से 31 दिसम्बर के बीच मदनमोहन मंदिर, विष्णुपुर के पास पश्चिमी बंगाल में आयोजित यह महोत्सव, अपने खूबसूरत टेराकोटा मंदिरों सिल्क की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता स्थानीय हस्तशिल्प और संगीत है। विष्णुपुर अपने स्वयं के शास्त्रीय संगीत के घराने के लिए भी प्रसिद्ध है।

सांस्कृतिक उत्सवों का दिसम्बर जाने पर और जनवरी आने की पूर्व संध्या पर कुछ लोग नववर्ष मनाते हैं। पर मेरी 94वें साल में चल रही अम्मा कहतीं हैं कि ये हमारा नया साल नहीं है। अब अम्मा की बात तो माननी है न।

(लेखिका, पत्रकार, ब्लॉगर, ट्रैवलर है)

ISSN No. 2581-3528

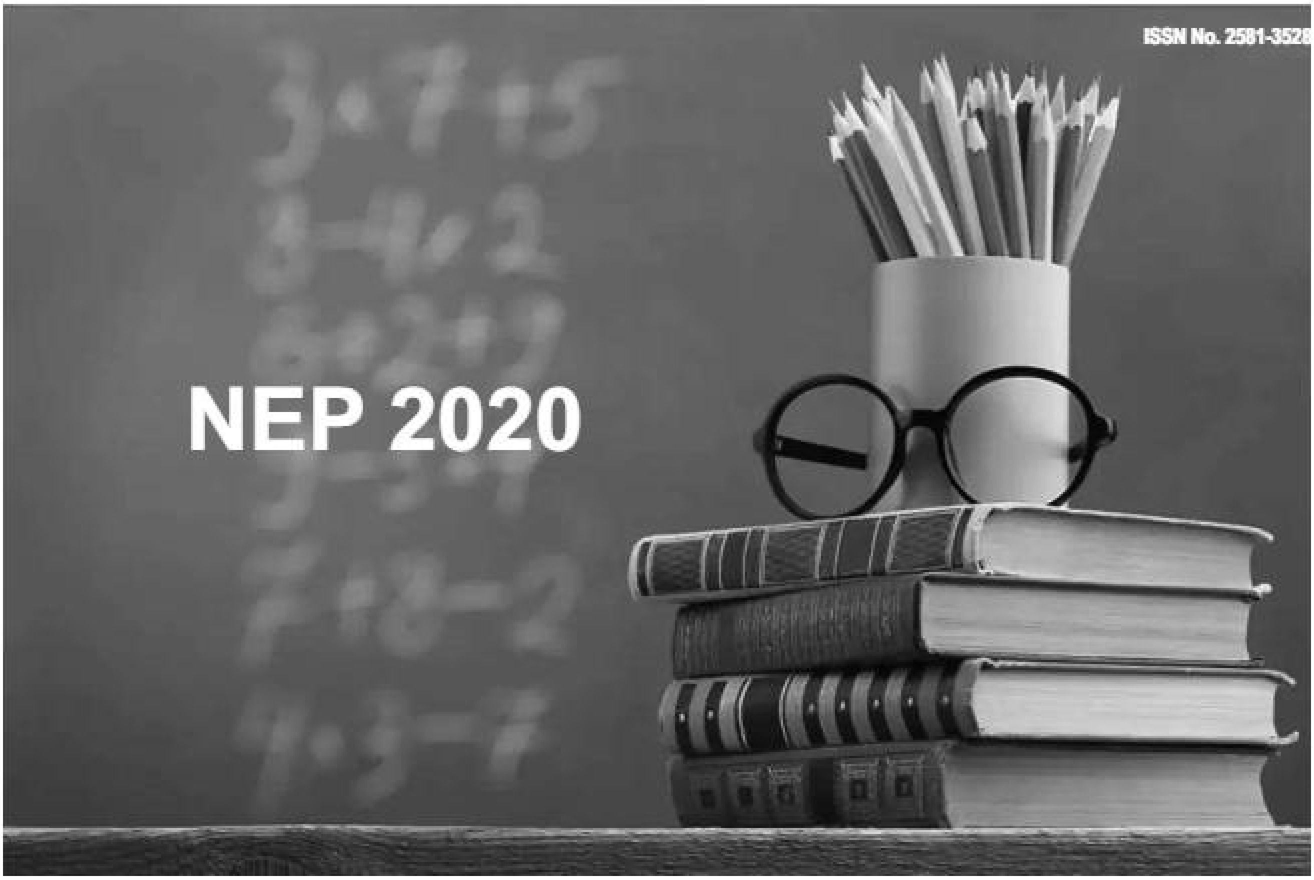

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : भविष्य का भारत

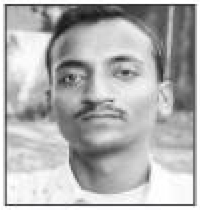

मोहित कुमार

भारतीयता की महान विरासत से युक्त, महात्मा गांधी के विजन से अनुप्राणित, डॉ. बीआर आम्बेडकर के दिए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। आजाद भारत की श्रृंखला में प्रथम शिक्षा नीति 1968 में 'डीएस कोठारी' की अध्यक्षता में बनी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी और 1992 में उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी किए गए। दरअसल नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन् 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक 'के. कस्तूरीरंगन' की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। भारतीय विद्वतजनों, शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसरण के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था का स्वर्णिम बदलाव है। भारत के प्रतिभाशाली विश्लेषकों और पथ प्रदर्शकों के अनुमोदन और विमर्श के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश के प्रतिभाशाली जनजीवन के समक्ष पेश किया गया। दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश के चारों दिशाओं से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 676 जिलों के शिक्षकों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, अभिभावकों और छात्रों से सुझाव और मंथन कर जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 साकार हुई है। राष्ट्र की प्रभुत्वता और लोकतांत्रिक गतिविधियों के अवलोकन कर विधिवत/नियमानुसार प्रस्तुत होने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। 21वीं सदी में भारत की शिक्षा व्यवस्था ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अद्भुत ज्ञान की पराकाष्ठा में व्याप्त जीवन की नई शुरुआत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक ओर जहां शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान खामियों को दूर करने का प्रावधान है, तो दूसरी ओर 21वीं सदी के बदलते हुए भारत की आंतरिक और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की तैयारी भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ एक अन्य नया परिवर्तन भी हुआ, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया, जो सर्वथा उचित है। 'मानव संसाधन' से ध्वनित होता है कि मानवीय भावों–संस्कारों से रहित इंसान जैसे एक भौतिक संसाधन मात्र हो, जो पश्चिम के भौतिकवादी चिन्तन से प्रेरित है। जबकि 'शिक्षा' अभिधान मनुष्य के भौतिकवादी पहलु के साथ–साथ सांस्कृतिक, चारित्रिक और मनोवैज्ञानिक सभी पक्षों को समाहित करता है, जो भारतीय

ISSN No. 2581-3528

चिंतन–पद्धति का प्रतिबिम्बन है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भविष्य के भारत का स्वर्णिम बदलाव : 1968 में पहली शिक्षा नीति का प्रस्तुतीकरण हुआ, डीएम कोठारी की अध्यक्षता में यह भी स्पष्ट किया गया था कि पांच साल में शिक्षा नीति का रिव्यू किया जाएगा। 1986 तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। दूसरी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 29 जुलाई 2020 को प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसे राष्ट्र की विविधता में समावेश किया गया। इस शिक्षा नीति में प्रथम कक्षा से उच्च स्तरीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रथम से पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भारतीय भाषा यानि मातृ भाषा का अध्यापन करवाने पर जोर दिया गया है। भारतीय भाषाओं का अनुसरण करवाना व मातृ भाषा का अधिकतम प्रचलन करना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में 'भारतीय भाषाओं के अध्यापन' पर बल दिया गया है। एक महत्वपूर्ण अनुशंसा है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पांचवी ग्रेड तक की पढ़ाई होगी, जिसे आठवीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। अंग्रेजी होगी अब भी, लेकिन अब सिर्फ एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। शैक्षणिक मनोविज्ञान के अनुसार मातृभाषा में सीखना आसान होता है क्योंकि इसमें सम्प्रेषण व संज्ञान सहज व शीघ्र होता है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चा समझता है जबकि इतर भाषाओं में उसे रटना पड़ता है। यह अनायास नहीं है कि संसार के हर विकसित देश में स्कूली शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही होती है। यहां तक की उच्च शिक्षा का माध्यम भी सामान्यतया उनके देश की भाषा होती है। एनईपी का यह बिंदु भारतीय भाषाओं और संस्कृति दोनों की मजबूती की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 'सबका साथ, सबका विकास' को साकार करने की दिशा में 'सबको शिक्षा' देने की महत्वकांक्षी योजना के साथ लागू की गई। इसमें 'राइट टू एजुकेशन' को 14 साल से आगे बढ़ाकर 100 प्रतिशत जीईआर के साथ माध्यमिक स्तर तक 'एजुकेशन फॉर ऑल' का लक्ष्य रखा गया है। सन 2030 तक 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होगी। यही नहीं हमारे युवाओं की ऊर्जा का उचित उपयोग हो, इसके लिए उच्च शिक्षा में 2035 तक 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। उन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए इधर–उधर भटकना न पड़े इसके लिए 2030 तक लगभग हर जिले में कम से कम एक बहुविषयक वृहत उच्च शिक्षा संस्थान निर्माणित किए जाएंगे। सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े–वंचित तबकों के लिए भी नई शिक्षा नीति सजग व सरल है।

एससी–एसटी, ओबीसी, दिव्यांगों और गरीब वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए विशेष प्रावधानों का खाका तैयार किया गया है। सार्वजनिक के अलावा निजी क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इनके लिए निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृति के लिए प्रयास जारी करने का प्रावधान लागू किए जाने की संभावना है। निजी संस्थानों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए एक कैपिंग भी चलाया जाएगा, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्य शिक्षा मंत्रालय मॉनिटरिंग करेंगे। निजी शिक्षण संस्थानों में शुल्क सामान्य रखी जाएगी। सार्वजानिक या निजी सभी शिक्षा संस्थानों को ऑडिट और प्रकटीकरण के समान मानकों को भी निर्धारित किया जाएगा। पूर्व में मैकाले मॉडल पर आधारित शिक्षा किताबी ज्ञान व शैक्षणिक पाठ्यक्रम पर जोर देती थी। जो पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने वाले बेरोजगारों की बड़ी खेप तैयार कर रही थी। लेकिन एनईपी पाठ्योत्तर क्रियाकलापों और वोकेशनल शिक्षा पर भी बल देती है। महात्मा गांधी के श्रम–सिद्धांत के अनुरूप छठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 'कोडिंग' जैसे आधुनिकतम वोकेशनल प्रशिक्षण भी शामिल होंगे।

मल्टी–एंट्री और मल्टी–एग्जिट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की एक नई विशेषता होगी। अभी तीन वर्षीय ग्रेजुएशन में यदि छात्र को किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ना पड़े तो सारा परिश्रम, धन तथा समय बेकार चला जाता है। अब एक साल अथवा दो साल में भी पढ़ाई छोड़ने पर उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जरुर मिलेगा। बल्कि एक तय सीमा में वापस आकर वह अपनी बची पढाई पूरा कर सकता है। 'एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' एनईपी का एक अन्य क्रांतिकारी प्रावधान है। यह एक डिजिटल क्रेडिट बैंक होगा, जिसके द्वारा किसी एक संस्थान या प्रोग्राम में प्राप्त क्रेडिट को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा। किन्हीं मज़बूरी में संस्थान या शहर बदलने वाले विद्यार्थियों के लिए यह बहुत आश्वस्तकारी साबित होगा।

यह सर्वविदित है कि किसी राष्ट्र की प्रगति में शोध–अनुसंधान की बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए मोदी सरकार, अटल सरकार के 'जय विज्ञान' से आगे जाकर 'जय अनुसंधान' को एनईपी में बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध दिखती है। देश में एक मज़बूत शोध–अनुसंधान संस्कृति तथा क्षमता विकसित हो, इसके लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान भी शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा में एकीकृत एवं समन्वित नीति व लक्ष्य निर्धारण हेतु विभिन्न निकायों का विलय करके एक सिंगल रेगुलेटर 'भारत उच्च शिक्षा आयोग'का गठन किया गया। समग्रता में देखें तो लोकल से लेकर ग्लोबल, भारत केंद्रितकता से लेकर वैश्विकता, रोजगार से लेकर अनुसंधान और चरित्र निर्माण से लेकर भौतिक उपलब्धिकृत सभी दृष्टियों से उच्च लक्ष्यों वाली एनईपी 21वीं सदी में भारत की जरूरतों–चुनौतियों को पूरा करने की दिशा में एक दूरदर्शी विजन डॉक्युमेंट है।

(लेखक न्यूज 24 नोएडा में प्रड्यूसर, रिसर्चर, है)

ISSN No. 2581-3528

आदर्श हिन्दू परिवार

सतीश शर्मा

हिन्दू संस्कृति में परिवारों को संस्कृति व संस्कारों के संरक्षण और प्रसार के विस्तारक के रूप में माना जाता रहा है। परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में देखा जाता है। परिवार सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका व्यक्ति के जीवन को संवारने मे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। परिवार सामाजिक संगठन की एक सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक व्यक्ति निर्माण की इकाई है। परिवार के द्वारा ही आपसी संबंधों का निर्माण होता है। समाजशास्त्र में परिवार को समाज के लिए एक जरूरी घटक माना है। इस समय संयुक्त परिवार तेजी से टूटकर एकल परिवारों में बदल रहे हैं। एकल परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होता है, लेकिन इसमें सहनशीलता, परस्पर सहयोग व संस्कारों की कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जिसके कारण परिवार का प्रत्येक सदस्य चिंता से ग्रस्त हो रहा है। हमारी प्राधीन ऋषि–मुनियों की संस्कृति तो हमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की शिक्षा देती है अर्थात् पूरी पृथ्वी व इसमें रहने वाले सभी प्राणी, जानवर व वनस्पति परिवार के विभिन्न अंग है एवं इनके साथ मिलजुलकर रहना सिखाती है। हम अपने घरों में बच्चों को अच्छे संस्कार, माता–पिता के चरण स्पर्श, पूजा पाठ करना, बड़ों का सम्मान, छोटों से स्नेह, अपने कार्य की प्रति निष्ठा, समाज व देश सेवा की प्रतिदिन शिक्षा देनी चाहिए।

हम पश्चिमी संस्कृति अपना रहे है और अपनी संस्कृति को भूल रहे है। जबकि विदेशी हमारे देश व भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित हो रहे है। हिंदू संस्कृति सनातन है सनातन का अर्थ है शाश्वत। हमारी सभ्यता सनातन सभ्यता प्राचीन है लेकिन नवीनता को अपनाने की इसमें बहुत सामर्थ है। अपने बच्चों का ध्यान रखना बुजुर्गों का सम्मान करना यह हमारे परिवारों में ही सिखाया जाता है। भारतीय परिवार व्यवस्था में तो भोजन को प्रसाद कहा जाता, घर को मंदिर कहा जाता है। हमारी रसोई में पहली रोटी गाय के लिए होती है भगवान को भोग लगा कर सबसे पहले घर के बुजुर्ग को भोजन कराया जाता है और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालते हैं। सभी जीवो की चिंता करना हमारी संस्कृति की पहचान है। आज जब विदेशों में हर छोटी–छोटी बात पर तलाक लेने की परंपरा चल निकली है लेकिन हमारे यहां इसका अनुपात काफी कम है कुछ जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी वैवाहिक पद्धति में तलाक शब्द का उल्लेख भी नहीं है अगर एक बार संबंध बन गए जीवन भर निभाने की सौगंध दिलाई जाती है। सात जन्म का साथ है ऐसा कहा जाता है।

संयुक्त परिवार का अपना लाभ है, कमजोर व्यक्ति भी वहां पर अपने आपको बेसहारा महसूस नहीं करता जबकि एकल परिवार होने के कारण से आज जो आत्महत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं उनका कारण है कि हम अकेले होते हैं और अगर परिवार पर जरा सी भी समस्या आई तो कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता और हम अपने जीवन को अंत करने की तरफ चले जाते हैं। यह ठीक है कि आज महानगर

संस्कृति के कारण से छोटे मकान हो गए हैं लेकिन अगर हम साथ भी नहीं रह पाते तो हमें चाहिए कि अपने आनंद हम एक साथ मनाए दिवाली होली बसंत पंचमी इत्यादि जितने भी त्यौहार है हमें साथ मिलकर मनाने चाहिए। परिवार व्यवस्था को हमें खुद ही बचाना है। अगर परिवार व्यवस्था बचेगी तो आप समझिए हम पूरी एक सभ्यता को बचा कर रखेंगे। और उसको बचाने के लिए हमें करना क्या है इस पर विचार करना होगा। आज हमको सिर्फ इतना करना है कि हम सब एक साथ मिलकर भजन करें, एक साथ मलकर घूमने जाए। कोई ना कोई खेल परिवार के सभी सदस्य मिल कर खेले। परिवार के सभी सदस्य सप्ताह में एक मिलकर घर की सफाई करें।

हर परिवार में एक पैतृक कार्य होता है वह काम भी सिखाया जाना चाहिए। अपने बच्चों को अपने कुल देवता, कुलदेवी कौन है इसकी जानकारी दे व उनको उनके मंदिर लेकर जाए। बचपन से बच्चे को अपने साथ मंदिर लेकर जाना चाहिए इससे उसको भी मंदिर जाने की आदत पड़ेगी। पूजा पाठ व मांगलिक कार्य परिवार के सभी सदस्यों को साथ बैठकर करना चाहिए। घर में एक पूजा का स्थान रहे व तुलसी का पौधा लगाये। अपने घर में धार्मिक ग्रन्थ रखें। गीता, रामायण व अन्य को पढ़ें और इन पर परिवार के साथ चर्चा करें। घर के द्वार पर मांगलिक चिन्ह जैसे ॐ, स्वास्तिक इत्यादि लगाये। समाचार पत्र पढ़ें और देश व विश्व की वर्तमान परिस्थिति पर परिवार के सदस्यों के साथ जानकारी सांझा करे। घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान का परिचय बच्चों से कराएं और बच्चों का परिचय मेहमान से कराएं। दादा–दादी, मामा–मामी, चाचा–चाची, नाना–नानी ,ताऊ–ताई, बुआ–फूफा बहन–जीजा इनके साथ बच्चों को बात करने का मौका दें। कुछ ऐसे भी काम/बाते होते/होती है जो नहीं करने चाहिए अपने बच्चों को बताना चाहिए। हमारे पड़ोसी कौन हैं, क्या करते हैं.. उनकी आस्था कहां है इसकी जानकारी रखनी चाहिए व उनके साथ मधुर सम्बन्ध रखे। ऐसे रिश्तेदार मित्र हैं जो हमारे घर आते हैं हमे भी उनके घर जाना चाहिए। हम को अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, व मित्रों के सुख–दुख में साथ रहना व उनकी समस्याओं को समझना और उनकी समस्या को समझ कर उसके समाधान का प्रयास करे।

अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार कर उनके व्यवहार को और उनके कार्य को समझ कर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके साथ बातचीत करे, उनके अनुभव का लाभ उठाने का प्रयास करें। परिवार के किसी में विशेषकर बच्चों में कहीं कोई कमी हो सकती है कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं यदि हम बच्चों के सामने उनकी कमियों की चर्चा किसी अन्य से करेंगे तो बच्चे की कमी दूर करने के स्थान पर बच्चे जिद्दी हो जाएंगे और अपना आत्म स्वाभिमान खो देंगे। अतः हमको चाहिए कि बच्चों के विकास के लिए उनके अंदर उत्साह का संचार करे उनके गुणों को निखारने व बढ़ाने का प्रयास करे। पति–पत्नी आपस में एक दूसरे का उपहास ना उड़ाए कम से कम बहार वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं।

अगर घर में बच्चा पढ़ रहा हो तो अच्छा यह रहेगा कि हम टीवी बंद कर दे 1 सब मिलकर काम करेंगे सब मिलकर भजन करेंगे सब मिलकर भोजन करेंगे तो हमारा परिवार दिन प्रतिदिन आगे बढता चला जाएगा। एक साथ मिलकर कहीं बाहर जाकर आयोजन करें कभी कभी फिल्म देखने जाएं, कभी कभी किसी अन्य मनोरंजक कार्यक्रम व मेला को देखने जाए। प्रश्न यह है कि परिवार को अगर संभालना है तो हमको परिवार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और परिवार में सामूहिक जिम्मेदारी का भाव प्रकट करना पडेगा। जब हम सामूहिक जिम्मेदारी का भाव परिवार में बनाएंगे तो निश्चित ही हमारा परिवार सुखी परिवार होगा।

(लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नोएडा केशव भाग के संघचालक हैं)

केशव संवाद

केशव संवाद मासिक पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ें एवं केशव संवाद को सोशल मीडिया पर FOLLOW करें।

FACEBOOK

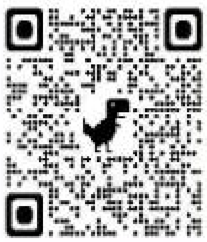

Keshav Samvad @keshavsamvad @KeshavSamvad samvadkeshav

ISSN No. 2581-3528

सोशल मीडिया की शक्ति

डॉ. शिल्पी जिंदल

आज के दौर में सोशल मीडिया जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका हैं। यह एक विशाल नेटवर्क हैं, जो कि सारे संसार को जोड़े रखता हैं। बीसवीं सदी की समाप्ति तक दुनिया में सशक्त मीडिया माध्यमों का तीव्र गति से विस्तार हुआ हैं। मीडिया के बदलते आयामों को देखकर ऐसा प्रतीत होता हैं कि मौजूदा समय बदलाव का समय हैं। संप्रेषण के ऐसे नए तरीके और नए माध्यम सामने आए हैं जो पूरी तरह हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लोगों को और विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाला सोशल मीडिया ऐसा ही एक माध्यम हैं, जिसे हमने जीवन के वक अटूट हिस्से के रूप में अपनाया हैं। यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को तय कर रहा हैं। वर्तमान संदर्भो में इसकी उपयोगिता को देखकर कहा जा सकता हैं कि इस दौर की एक बड़ी जरुरत और हकीकत बन चुका है सोशल मीडिया।

सोशल मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा करता हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश आदि को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता हैं। सोशल मीडिया के जरिये ऐसे कई विकासात्मक कार्य हुए हैं, जिनसे लोकतंत्र को समृद्ध बनाने का काम हुआ हैं, जिससे किसी भी देश की एकता, अखंडता, पथनिर्पेक्षता, समाजवादी गुणों में अभिवृद्धि हुई हैं।

सोशल मीडिया को परस्पर संवाद का वेब आधारित एक ऐसा अत्यधिक गतिशील मंच कहा जा सकता हैं, जिसके माध्यम से लोग संवाद करते हैं, आपसी जानकारियों का आदान–प्रदान करते हैं और उपयोगकर्ता जनित सामग्री को सामग्री सृजन की सहयोगात्मक प्रक्रिया के एक अंश के रूप में संशोधित करते हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत में 25 साल से अधिक की आबादी 50 प्रतिशत है। वास्तविक जीवन में मुलाकातें भले ही न होती हों, पर सोशल साइट्स पर हर किसी के हजारों मित्र हैं। फिल्म और क्रिकेट से जुड़े सितारे सोशल साइट्स पर लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और उनसे अपनी बातें सांझा कर रहे हैं। परंपरागत मीडिया भी अब फेसबुक व ट्विटर जैसे माध्यमों पर न सिर्फ अपने पेज बनाकर उपस्थिति दर्ज करा रहा है, बल्कि विभिन्न पदों पर लोगों द्वारा व्यक्त की गई राय को इस्तेमाल भी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अब विशेषज्ञों की राय समांतर सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत आमजन की राय भी ले रहा है। इस आभासी दुनिया के सहारे न सिर्फ मित्र बनाए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें वोट बैंक से लेकर व्यवसाय में धनार्जन हेतु भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अकादमिक बहसों का विस्तार अब फेसबुक व अन्य सोशल साइट्स पर भी होने लगा है। नारी विमर्श, बाल विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श इत्यादि सब कुछ यहां उपलब्ध है। आप इन्हें शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वाद–प्रतिवाद कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार नई बहसों को भी जन्म दे सकते हैं।

विचारों की दुनिया में क्रांति लाने वाले सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसकी न तो कोई सीमाएं है, न कोई बंधन। भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में न सिर्फ वैयक्तिक स्तर पर बल्कि राजनैतिक दलों के साथ–साथ कई सामाजिक और गैरसरकारी संगठन भी अपने अभियानों को मजबूती देने के लिए सोशल मीडिया का बखूबी उपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया सिर्फ अपना चेहरा दिखाने का माध्यम नहीं है बल्कि इसने कई पंक्तियों वैचारिक बहसों को भी रोचक मोड़ दिया है। जिन देशों में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है वहां अपनी बात कहने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया का लोकतंत्रीकरण भी किया है। हाल के वर्षो में अरब जगत में हुई क्रांतियों में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही। लोग इसके माध्यम से एक–दूसरे से जुड़े रहे और क्रांति का बिगुल बजाते रहे। इसके चलते राजसत्ताओं को यह पसंद नहीं आया। इसकी वजह से ईरान, चीन, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान और सीरिया ने इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया।

सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स आज एक स्टेटस सिंबल का प्रतीक बन चुका है, जिनकी अच्छाइयां और बुराईयां भी है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप सोशल मीडिया से क्या अपेक्षा रखते हैं? सोशल मीडिया आपको सोशल भी बना सकता है और एकाकी भी। सोशल मीडिया पर आप अपने पुराने मित्रों के साथ तरोताजा हो सकते हैं तो अनजाने लोगों के साथ धोखा भी खा सकते है। सोशल मीडिया पर आप दुनिया को अपनी अच्छाइयों व रचनात्मकता से रूबरू करा सकते हैं, तो दूसरो की बुराइयों को सीख भी सकते हैं। कोई भी माध्यम अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग करने वाले उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। यही बात सोशल मीडिया पर भी लागू होती है।

सूचना प्रोद्योगिकी विशेषज्ञ सैम पित्रौदा के अनुसार सूचना के आदान–प्रदान जनमत तैयार करने, विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों को आपस में जोड़ने, भागीदार बनने, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि नये ढंग से संपर्क करने में सोशल मीडिया एक सशक्त और बेजोड़ उपकरण के रूप में तेजी से उभर रहा है। यदि सरकारें उचित ढंग से लाभ उठाना सीख ले तो सोशल मीडिया उनके लिए अत्यन्त प्रभावकारी नीति उपकरण बन सकता है।

(लेखिका शम्भू दयाल पी. जी. कॉलेज, गाजियाबाद में अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर)

नवम्बर अंक की समीक्षा

आत्मनिर्भरता के पथ पर बढ़ने के लिए अपने राष्ट्र के आत्मस्वरूप को, शासन, प्रशासन व समाज को स्पष्ट तथा समान रूप से समझना अनिवार्य है अपने–अपने स्थान व परिस्थिति में अपने आधार पर बढ़ते समय आवश्यकता पड़ने पर कुछ लचीलापन धारण करना पड़ता है। विजयदशमी के अवसर पर परम पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी का वक्तव्य "भविष्य में भारत" के निर्माण में लगे कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करेगा, सभी को पढ़ना चाहिए। आज पूरा विश्व परम पूजनीय सरसंघचालक जी के उद्बोधन को बड़े ध्यान से सुनता है। "विकास के बारे में पश्चिम की अवधारणा अलग है और हमारे विकास के बारे में अलग कल्पना है हमें विकास की अवधारणा खड़ी करनी पड़ेगी" बहुत ही सटीक आर्थिक विश्लेषण किया है प्रो. अखिलेश मिश्र का लेख "भविष्य का भारतः चुनौतियां एवं संभावनाएं"। स्वदेशी आधारित अर्थनीति सबकी होनी चाहिए क्योकि अर्थनीति में अर्थ सुरक्षा स्वावलंबन के आधार पर होती है। लेख में गागर में सागर भरने का काम किया है। बाजार में रोजगार जैसी समस्याओं पर चर्चा या कोविड में भारत का प्रबंधन पढ़ने लायक है।

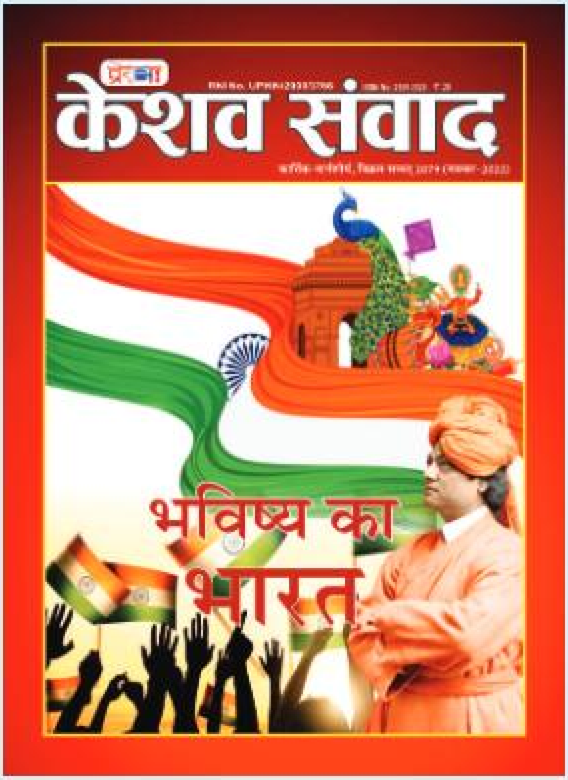

डॉ. गौरव अग्रवाल अपने लेख "वैश्विक परिवेश में भारत का भविष्य आर्थिक विश्लेषण" बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाने में कामयाब हुए है। "विकसित देशों के अर्थशास्त्री मानव विकास सूचकांक को आंकते समय न केवल भारत के आर्थिक विकास को पूर्णता नजरअंदाज कर रहे हैं बल्कि भारत में तेजी से कम हो रही गरीबी व आर्थिक असमानता पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं"। श्रीमान प्रहलाद सबनानी ने अपने लेख विकसित देशों की तुलना में भारत में तेजी से कम हो रही गरीबी पर लिखा है। डॉ प्रदीप कुमार का लेख 'भविष्य के भारत की गंभीर चुनौती है जनसंख्या बदलाव' एक बहुत ही विचार पूर्ण लेख है बड़े विस्तार से समझाया है की जनसंख्या परिवर्तन आर्थिक चुनौती के साथ यह एक सामाजिक चुनौती भी है। 'पुरातन विरासत हस्तिनापुर'– प्रो. हरेंद्र सिह, 'नवाचार मे उची उड़ान'– प्रमोद भार्गव, भारत सांस्कृतिक संदर्भ, –डॉ. उर्वीजा शर्मा, डिजिटल क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत–अनुपमा अग्रवाल, 'नारी शक्ति : समर्पण से सम्मान तक' –डॉ. प्रियंका सिह, भारत की ज्ञान परम्परा : विश्व गुरु के रूप में–श्री आशीष कुमार, मीडिया में तकनीक की चुनौतियां–श्री अमित शर्मा, डॉ. अक्षय के सिंह का लेख मीडिया, प्रोपेगंडा और वैश्विक फलक पर उभरते भारत कि चुनौतियाँ काफी प्रशंसनीय लेख है। युवा वर्ग को विशेष कर मीडिया से संबंधित लोगों को प्रशांत त्रिपाठी का लेख "युवाओं के लिए आदर्श प्रतिमान स्थापित करने में मीडिया की भूमिका" जरूर पढ़ना चाहिए। 'फिल्म मीडिया और समाज'– प्रो अमिताभ श्रीवास्तव, डॉ. राम शंकर ने अपने लेख "नए भारत की नई पत्रिकारिता" में लिखा है कि पत्रकारिता पूंजीपतियों के लिए धन कमाने और समाज एवं सरकार पर धौंस जमाने का हथियार बन गई है, 'सामाजिक समरसता के निर्माण में मीडिया की भूमिका'– प्रो पूनम कुमारी, पत्रकारिता में लगे खाज को कोढ़ मे बदलने से पहले ईलाज की जरूरत, –आशीष कुमार, मीडिया की लक्ष्मण रेखा– डॉ. अरविन्द कुमार पाल, भारतीयता की मूल भावना का संवर्धन और मीडिया–मोहित कुमार, इन सबके लेख पत्रकारिता कर रहे व करने के इच्छुक लोगों के लिए प्रेरणादायक है। नीलम भागी जी लेख कोई कहे गोविंदा, कोई कहे गोपाला, भगवान के विभिन्न रूपों का परिचय कराता है। संपादकीय में "भारतीय सनातन परम्परा के अनुरूप" भविष्य के भारत पर चर्चा या "डार्क वेब पर चल रहा जेहादी एजेंडा" युवाओं को दिशा देने का काम कर रहे है जोकि वर्तमान परिदृश्य में जरूरी है। विषय के अनुरूप साजसज्जा विशेष कर मुख्य पृष्ठ आकर्षित करता है।

अंत में कहना चाहूँगा की भारत बदल रहा है इस बदलाव के दौर में 'भविष्य का भारत" विषय पर चर्चा करना एक सकारात्मक कदम है। केशव संवाद पत्रिका युवा पत्रकार, लेखकों, व समाज परिवर्तन में लगे समाजसेवियों के लिए के एक उपयोगी पत्रिका है। **संयोजन : सतीश शर्मा**

सूर्या

आत्मनिर्भर भारत की पहचान

लाइटिंग | अप्लायेंसेस
पंखे | स्टील और पीवीसी पाइप

इनोवेशन, क्वॉलिटी और विश्वसनीयता हमारी पहचान।

सूर्या के प्रोडक्ट केवल पूरे भारत में ही उपलब्ध नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 50 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। कम्पनी सभी ग्राहकों की ज़िन्दगी रौशन करने तथा सभी से इनोवेशन, गुणवत्ता और विश्वसनीयता का वादा करती है।

सूर्या रोशनी लिमिटेड

ई–मेलः consumercare@surya.in | www.surya.co.in suryalighting surya_roshni
दूरभाषः +91–11–47108000, 25810093–96 | **टोल फ्री नंबरः 1800 102 5657**